खण्ड-149, अंक-2
सोमवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(21 फरवरी, 1955 ई0)

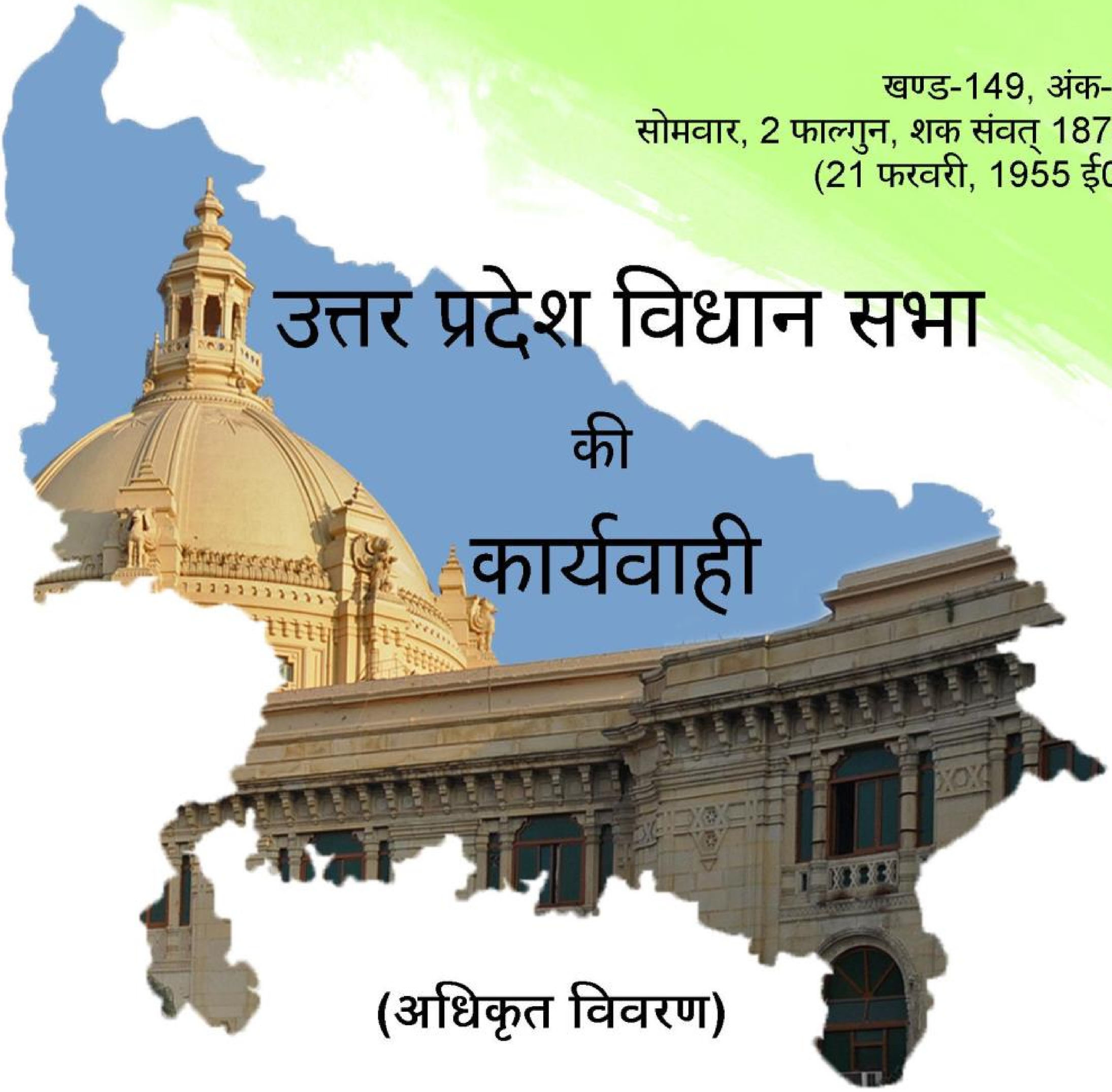

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 149 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २१ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन मे अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४१)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद, सिंह श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)

भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
(बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
(सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमूनासिंह, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री

रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअवतार तिवारी, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राना, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

संसदीय उपचुनाव के समय कानपुर से दफा १४४ हटाने का सुझाव

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह संसद उपचुनाव हो जाने तक के लिये कानपुर से दफा १४४ हटाने जा रही है ?

पुलिस उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—मैजिस्ट्रेट ने १४४ की आज्ञा स्थानीय परिस्थिति को देखते हुये जारी की। इस आज्ञा की अवधि २२ मार्च को समाप्त होती है। दफा १४४ जाब्ता फौजदारी में मैजिस्ट्रेट ही उस आज्ञा को वापिस ले सकता है। राज्य सरकार को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनको इस प्रकार की सूचना अथवा शिकायत मिली है कि इस दफा के लगे रहने की वजह से चुनाव के दैनिक कामों में काफी अड़चनें पड़ रही हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं, क्योंकि इस आज्ञा में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे चुनाव के कार्य में कहीं पर भी कोई बाधा पड़ती हो।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों से मुतवातिर यह दफा कानपुर में किसी न किसी बहाने लगी रहती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब जब जैसी परिस्थिति होती है, इस दफा को लगाया जाता है। यह सही नहीं है कि पांच वर्ष से बराबर लगी रहती है। बीच बीच में अक्सर जब परिस्थितियां ठीक रहीं, तो यह दफा हटा ली गई और फिर जब जरूरत पड़ी तो लगा दी गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर को राय देने की कृपा करेगी कि वह चुनाव होने तक धारा १४४ हटा ले ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मेरे ख्याल में तो शायद चुनाव के दिनों में इसकी जरूरत ज्यादा पड़े।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार कृपा कर यह बता सकती है कि कांग्रेस सरकार के रिजीम में, १५ अगस्त सन् ४७ के बाद से, कानपुर में कितने समय तक १४४ दफा नहीं थीं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि चुनाव संबंधी समितियां भिन्न-भिन्न स्थानों पर कानपुर में बराबर हो रही हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को यह पता है कि डा० राममनोहर लोहिया की मीटिंग जो कल कानपुर में हुई थी उसके लिये लगातार एक हफ्ते से इजाजत मांगने पर किसी तरह कल दो बजे मीटिंग की इजाजत मिली ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस १४४ के मुताबिक केवल सड़कों पर या मिल गेट के के सामने ही आवश्यकता पड़ती है कि इस बात की परमीशन मिले। पब्लिक पार्क्स, प्राइवेट प्लेसेज या ऐसी जितनी भी जगहें हैं जहां मीटिंग्स होनी चाहिये, वहां मीटिंग्स के लिये इस दफा में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है ?

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या विशेष कारण है कि कानपुर में दफा १४४ बराबर लगी रहती है ?

कुछ सदस्य—आपके ही कारण, आपके ही कारण ।

(सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कौन सी विशेष परिस्थिति है जिसके कारण १४४ दफा लागू की गई है और १४४ दफा जो लागू की गई है उसकी क्या क्या शर्तें हैं और क्या-क्या उससे रोक लगाई गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी अभी मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस १४४ के मुताबिक केवल सड़कों पर और मिल गेट के सामने ही प्रतिबन्ध है कि कोई मीटिंग वगैरह न हों क्योंकि सड़कों पर सब तरह के लोग रहते हैं, हर पार्टी के लोग और हर दल के लोग होते हैं। किसी समय भी उनमें भिड़ंत हो सकती है, वादविवाद हो सकता है और इससे अमन में काफी खलल पड़ सकता है। इसी प्रकार मिल गेट के सामने भी लोग आते हैं और जाते हैं, वहां पर भी इस बात की आशंका रहती है कि अमन में खलल पड़ सकता है। इसलिये इन दोनों ही जगहों के लिये यह प्रतिबन्ध है। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पब्लिक मीटिंग्स होती हैं और होती रहती हैं। सैकड़ों मीटिंग्स वहां हो रही हैं और हर दल की तरफ से हो रही हैं। किसी तरह की अड़चन वहां नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—यह सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डा० लोहिया की मीटिंग के लिये क्या इजाजत किसी मिल के सामने के लिये मांगी गयी थी या किसी पब्लिक पार्क के लिये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—डा० लोहिया की मीटिंग के लिये किस स्थान के लिये परमीशन मांगी गयी, इसका मेरे पास ब्योरा नहीं है। यदि आप पृथक प्रश्न करेंगे तो मैं सूचना मंगा दूंगा ।

तारांकित प्रश्न

हमीरपुर जिले में भूदान यज्ञ में दी गयी परती जमीनों का मुआवजा

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो परती जमीनें जमींदारी विनाश कानून लागू होने के पूर्व भूदान यज्ञ में दान दे दी गई, क्या उसका भी मुआवजा भूतपूर्व जमींदारों को दिया जायेगा ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं, जमींदारी विनाश कानून लागू होने के पूर्व भूदान यज्ञ में जो परती जमीनें दान में दी गईं उनका मुआवजा यदि कुछ हुआ तो भूदान यज्ञ समिति को दिया जावेगा ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो प्रदेश में इस प्रकार की कितनी एकड़ भूमि है तथा उसका कितना मुआवजा दिया जा रहा है या दिया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में इस प्रकार की कितनी परती जमीन है और उसका मुआवजा कितना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हमीरपुर जिले में जमींदारी विनाश कानून लागू होने के पूर्व २६२२.४० एकड़ परती भूमि भूदान यज्ञ में दान दी गई थी । इसका मुआविजा कुछ नहीं है क्योंकि उससे कोई आय नहीं होती थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी विनाश कानून लागू होने के पूर्व भूदान यज्ञ समिति में कितनी परती जमीन प्रदेश में दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिए आप नया सवाल करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी परती जमीन जिसका मुआविजा आया है और सरकार उसे देने वाली है, वह कितना मुआविजा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—परती जमीन की ज्यादातर आमदनी नहीं होती । शायद थोड़ी सी सायर की आमदनी हुई तो वह भी भूदान समिति को दी जायगी, वरना परती जमीन पर मुआविजा नहीं होगा ।

इलाहाबाद हरिजन आश्रम को कृषि विभाग द्वारा दिया गया धन

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ने १९४९-५० में इलाहाबाद हरिजन आश्रम के कृषि कार्य की उन्नति किये जाने के निमित्त कृषि विभाग द्वारा १०,००० रु० की सहायता दी ? अगर हां, तो इस धन का उपयोग योजनानुसार किया जा चुका है या नहीं ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—कृषि विभाग ने इलाहाबाद हरिजन आश्रम को सन् १९४८-४९ के लिये कृषि कार्य की उन्नति के हेतु १०,००० रुपये की धनराशि सहायता के रूप में दी थी, मगर आश्रम उपरोक्त धन को सन् १९४८-४९ में उपयोग में न ला सका और प्रार्थना किया कि विभाग द्वारा उस धनराशि को सन् १९५०-५१ में उपयोग करने की आज्ञा प्रदान की जावे । विभाग ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था । परन्तु, फिर भी मई सन् १९५२ तक आश्रम उस धन को उपरोक्त काम में खर्च न कर सका । तब सरकार ने उस रकम को वापस लेने की आज्ञा दी और वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार के पास शिकायतें आई हैं कि इस अनुदान और दूसरी सरकारी अनुदानों का दुरुपयोग हरिजन आश्रम के प्रबन्धकों ने किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—दुरुपयोग करने का तो सवाल इसलिये नहीं उठा कि वह रकम बैंक में जमा थी और अब वापस ली जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस अनुदान के संबंध में तथा अन्य अनुदानों के संबंध में इलाहाबाद हरिजन आश्रम में अभी हाल ही में कुछ गबन पकड़ा गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वहां गबन पकड़ा गया या नहीं, इसकी सूचना तो मुझे नहीं है, लेकिन जो मेरी इत्तला है वह यह है कि यह रुपया जो १० हजार दिया गया था वह बैंक में रखा हुआ है। उसका सूद वह ले रहे थे। इस सूरत से उसको दुरुपयोग कहा जा सकता है। जिस काम के लिये यह रुपया खर्च होता, उस में खर्च न करके उससे वह मुनाफा ले रहे थे। इस हद तक दुरुपयोग हो सकता है।

कुमायूं रोडवेज रीजन का तोड़ा जाना

*५—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमायूं रोडवेज को पुनः एक रीजन के रूप में संगठित किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पहले कुमायूं में एक रोडवेज रीजन अलग से बना हुआ था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसको तोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माइलेज बहुत कम था और खर्चा ज्यादा पड़ता था, इसलिये उसे तोड़कर बरेली में मिला दिया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कुमायूं रीजन को तोड़े जाने से सरकार को कितनी बचत हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार को करीब ३९,२१० रुपये की बचत हुई।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य शांति रखें और बातचीत न करने की कृपा करें।

नैनीताल जिले में रामगढ़-मुक्तेश्वर रोड पर रोडवेज की गाड़ियां चलाने का विचार

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल जिले में रामगढ़-मुक्तेश्वर मोटर रोड के बन जाने के बाद अभी तक उपर्युक्त महत्वपूर्ण रोड पर रोडवेज बसें नहीं चलाई जा रही हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नैनीताल जिले के रामगढ़-मुक्तेश्वर मार्ग पर रामगढ़ से सतभंगा तक रोडवेज की बसें चल रही हैं। शेष मार्ग पर भी रोडवेज की गाड़ियां चलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि डेढ़ साल से मोटर मार्ग के बन जाने पर भी अभी तक इस रोड पर बसेज नहीं चलाई जा रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क पहले पक्की नहीं बनी थी जो अब बनी है। इसलिये जहां तक सतभंगा से मुक्तेश्वर तक पक्की सड़क थी वह रोडवेज में ले ली गई थी बाद में बाकी को भी पक्की सड़क बन गई और उसको भी क्लासीफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन प्रायवेट मोटर आपरेटर्स के झगड़े चले और नई सड़कों के लेने के सवाल को रोक दिया गया। अब जब यह कानून बन जायगा तब इस पर विचार किया जायगा कि इसको लिया जाय या नहीं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि मुक्तेश्वर की सड़क अभी तक कच्ची है उस पर सरकार प्रायवेट आपरेटर्स को बस चलाने देने के सवाल पर सोच रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी बतलाया गया कि जितनी पक्की सड़क बन गई है उसके क्लासीफाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इस कानून के बन जाने पर विचार किया जायगा कि इस सड़क को लिया जाय या नहीं ?

*७-८—श्री गेंदा सिंह—[२१ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

पशु मेलों को सरकारी प्रबन्ध में लेने का विचार

*९—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार प्रदेश के पशु मेलों पर अपना कब्जा कर लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और क्यों ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्यों लेना चाहते हैं, इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—यह तो विचाराधीन है, यह उपमंत्री जी कह रहे हैं। जब तय ही नहीं हुआ तो बतलायेंगे कैसे ?

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कब तक विचाराधीन रहेगा, यह बताना मुश्किल है।

श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस योजना में वे भी मेले हैं जो कि कुछ लोग अपनी सीर और खुदकाश्त में लगाते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ये सब मामले विचाराधीन हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि सार्वजनिक भूमि पर पशु मेले लगाने वाले जो पहले से थे उनको बहुत से सीर और खुदकाश्त करने वालों ने अपनी जमीन उजाड़ कर लगा लिये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसा हुआ होगा।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि यह प्रश्न सरकार के सामने कब से विचाराधीन है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह कुछ दिनों से विचाराधीन है।

दोहरीघाट (आजमगढ़) के समीप बस दुर्घटना

*१०—श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि दोहरीघाट (आजमगढ़) के समीप एक रोडवेज बस के पेड़ से टकरा जाने के कारण १ महिला मरी और ७ व्यक्ति सख्त घायल हो गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इस दुर्घटना में एक महिला मरी और १४ यात्रियों को चोटें आईं, घटना के कारण की जांच-पड़ताल जिलाधीश द्वारा कराई गई है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधीश की रिपोर्ट में और क्या बातें थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिलाधीश की रिपोर्ट अभी तक आयी नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या यह सही है कि दुर्घटना होने का कारण यह था कि ड्राइवर शराब पिये हुये थे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो कह दिया गया है कि रिपोर्ट नहीं आयी है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो इस महिला की मृत्यु हुई है उसके सम्बन्धियों को सरकार ने मुआविजे के रूप में कुछ रुपया दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मुआविजे का सवाल भी जिलाधीश की रिपोर्ट आने पर तय होगा।

यू० पी वरोडवेज सेण्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के एक मैकेनिक की मोटर दुर्घटना में मृत्यु

*११—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यू० पी० रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप (कानपुर) का एक मैकेनिक ट्रक से कुचल कर मर गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा— जी हां। श्री हरनाम सिंह Helper Fitter, Body Building की एक प्राइवेट ट्रक से कुचल कर मर जाने की सूचना मिली है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्राइवेट ट्रक के मालिक के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी भी कोई रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आयी। इसके अलावा यह मामला दूसरे मुहकमे से ताल्लुक रखता है, हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

गढ़वाल जिले में रैम सेंटर ऊखीमठ और जोशीमठ पर व्यय

*१२—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रैम सेन्टर, ऊखीमठ और जोशीमठ जिला गढ़वाल में कितनी भेड़ और बकरियां, किस जाति की कब भेजी गई हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऊखीमठ और जोशीमठ रैम सेन्टर्स, जिला गढ़वाल में रामपुर बुशायर जाति के २१ और २२ भेड़ें अप्रैल और मई सन् १९५४ में भेजे गये हैं। वहां बकरियां कभी भी नहीं भेजी गईं।

*१३—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त प्रत्येक केन्द्र में भेड़-बकरियों के लिये और कर्मचारियों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं और उनके बनाने में क्या व्यय हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऊखीमठ रैम सेन्टर में एक मंजिल के दो कमरे और बाड़ा २,००० रु० की लागत से वर्ष १९५२–५३ में बनवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त इस मकान की छत खराब होने के कारण फरवरी, सन् १९५४ में बदली गई, जिसमें १८५ रुपये की लागत लगी जो जिला नियोजन अधिकारी, गढ़वाल ने खर्च किया। इसमें एक कमरा भेड़ों के लिये तथा दूसरा स्टोर व कर्मचारियों के वास्ते है। भेड़ों के साथ अनवाल (गड़रिया) भी रहते हैं जैसा कि पहाड़ का रिवाज है।

जोशीमठ रैम सेन्टर में दो कमरे और एक बाड़ा निचली मंजिल में तथा दो कमरे एक बरान्डा ऊपरी मंजिल में है। निचली मंजिल में एक कमरे में भेड़ें और दूसरे में अनवाल रहते हैं और ऊपर मंजिल में एक कमरे में स्टोर है और दूसरे में स्टाकमैन रहता है। यह मकान १९९५ रुपये की लागत का बना है। वहां एक शीप डिपिंग टैन्क भी बना है जिसकी लागत ७०० रुपये की है।

*१४—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त केन्द्रों में कितने कर्मचारी रखे गये हैं और उन पर मासिक क्या खर्च होता है तथा प्रत्येक केन्द्र के रखरखाव में वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हर एक केन्द्र पर एक स्टाकमैन एक जमादार अनवाल और एक अनवाल नियत है जिन पर मासिक व्यय इस प्रकार है :—

		वेतन	महंगाई	जोड़
		रु०	रु०	रु०
(१) हेड अनवाल	..	३०	२०	५०
(२) अनवाल	..	२०	२०	४०
				९०

वार्षिक रखरखाव का व्यय १,७५० रु०।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इन रैम सेंटरों पर अंगोरा और मेरौना जाति की भेड़ें क्यों नहीं भेजी गयी हैं, रामपुर बुशेर जाति की भेड़ें क्यों भेजी गयी हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी— यही मुनासिब समझा गया कि वह भेड़ें वहां भेजें।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि गढ़वाल की भेड़ें और रामपुर बुशैर नस्ल की भेड़ों में कोई विशेष अन्तर नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अन्तर तो है। वरना दो जातियां न होतीं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि पीपलकोठी सेंटर पर मेरौना और अंगोरा जाति की भेड़ों पर जो एक्सपेरीमेंट किया गया है वह सफल हुआ है और उसी जाति की भेड़ें जिला गढ़वाल में पनप सकती हैं ? यदि हां, तो अन्य सेंटरों में यह भेड़ें क्यों नहीं भेजी जा रही हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कौन सी भेड़ कहां होगी इसका एक्सपेरीमेंट हो रहा है और जब पूरे तौर से यकीन हो जायगा कि वहां वह रह सकती है तो वहां भेजी जायंगी।

बबीना थाना, जिला झांसी के अन्तर्गत मिलिटरी की जमीन

*१५—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)— क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायतें आई हैं कि बबीना थाना (झाँसी) के अन्तर्गत जो भूमि मिलिटरी के उपयोग में है उनका भी लगान ग्रामवासियों से वसूल किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। परन्तु जिलाधीश झांसी के पास इस आशय की कुछ शिकायतें आई हैं। ग्रामवासी बहुत सी ऐसी भूमि का उपयोग कर रहे हैं जो अस्थायी रूप से मिलिस्ट्री के लिये ली जा चुकी है। जिस भूमि का ग्रामवासी उपयोग कर रहे हैं उनसे उस भूमि का लगान वसूल किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसी भी जमीन है जिस पर मिलिटरी वाले खेती करते हैं और उसका लगान किसानों से वसूल किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मिलिटरी वाले कोई खेती नहीं करते।

फ्लाइंग क्लब्स को सहायता

*१६—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने Flying Clubs हैं और उनको सरकार कितनी प्रतिवर्ष सहायता देती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उत्तर प्रदेश में केवल एक Flying Club लखनऊ में है, जिसकी २ शाखाएं इलाहाबाद तथा कानपुर में हैं, प्रतिवर्ष सहायता की दर निश्चित नहीं है, सन् १९५४–५५ में सरकार ने क्लब को ५,२८,००० रु० की सहायता प्रदान की।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस फ्लाइंग क्लब से प्रतिवर्ष कितने ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सूचना तो मेरे पास नहीं है सूचना मिलने पर पता लगाया जा सकता है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—इसको जो रुपया दिया जाता है इसके अलावा भी जो उनके अधिकारी हैं उनको भी कुछ अनुदान दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा— जी नहीं, यही सहायता दी जाती है इसके अलावा और कोई चीज नहीं दी जाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि यह अनुदान जो फ्लाइंग क्लब को दिया जाता है वह ठीक तरह से खर्च किया जाता है या नहीं, इसको देखने के लिये सरकार की ओर से कोई साधन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—फ्लाइंग क्लब का जो डाइरेक्टरेट है उसमें २ आदमी सरकार की तरफ से नामिनेटेड हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फ्लाइंग क्लब से निकलने के बाद सब ट्रेनीज, ट्रेनिंग पा जाने के बाद काम पर लग जाते हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, कुछ लोगों को लिया जाता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तो क्या सरकार फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग पाने वाले नवयुवकों की संख्या भी इस प्रकार की निर्धारित करने की कृपा करेगी कि उनको ट्रेनिंग पाने के बाद उचित स्थान पर नौकरी मिल जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इस पर विचार किया जायगा।

श्री वीरेंद्र वर्मा— क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस फ्लाइंग क्लब में नवयुवकों के साथ नवयुवतियों को भी ट्रेनिंग दिये जाने का कोई प्रबन्ध है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, अगर कोई आवे तो इन्कार नहीं हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह अनुदान फ्लाइंग क्लब को दिया जाता है वह इस्टेब्लिशमेंट के लिये दिया जाता है या जो हमारे पायलेट को ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिये दिया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह अनुदान कोई खास खर्चे के लिये नहीं दिया जाता है सारी की सारी ग्रान्ट जो दी जाती है वह क्लब को चलाने के लिये दी जाती है जिसमें ट्रेनिंग और अन्य बातें शामिल रहती है जिस तरह से चाहें वह खर्च करें।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फ्लाइंग क्लब में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें सब हिन्दुस्तानी हैं या बाहर के भी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां तक मुझे मालूम है सब हिन्दुस्तानी ही हैं।

*१७–१८—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[२१ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में कन्सालीडेटर्स के चुनाव में हरिजन व पिछड़ी जातियों के लोग

*१९—**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में तारीख १८ सितम्बर, १९५४ को जो चुनाव कन्सालिडेटर्स का हुआ है उनके लिये कितनी दरख्वास्तें हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों की थीं और उक्त जातियों के कुल कितने-कितने उम्मीदवार लिये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला जौनपुर में कन्सालीडेटर्स के चुनाव के लिए जो १८ सितम्बर, १९५४ ई० को हुआ था केवल एक प्रार्थना-पत्र हरिजन उम्मीदवार का और १० प्रार्थना-पत्र पिछड़ी जातियों के आये थे। उनमें से एक हरिजन और दो पिछड़ी जाति के उम्मीदवार चुने गये।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल दरख्वास्तें कितनी थीं और उसमें से कुल कितने उम्मीदवार लिये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बतला दिया कि एक हरिजन की थी और १० पिछड़ी जातियों की थीं।

*२०–२१—**श्री बाबू नन्दन**—[२१ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

डिप्टी केन कमिश्नर मार्केटिंग का रिक्त स्थान

*२२—**श्री मही लाल** (जिला मुरादाबाद)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्केटिंग डिप्टी केन कमिश्नर का स्थान कितने दिन से रिक्त है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—डिप्टी केन कमिश्नर मार्केटिंग का स्थान जनवरी, १९५५ के दूसरे सप्ताह से रिक्त है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस स्थान की पूर्ति वह कब तक करने जा रहे हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अभी जनवरी में यह खाली हुई है और कोशिश की जा रही है कि वह जल्दी ही पूरी हो जाय।

*२३—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[२१ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद से दिये गये मोटर लारी तथा ट्रक के परमिट

१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रांसपोर्ट कमेटी तथा ट्रांसपोर्ट आफिसर द्वारा कितने मोटर लारी तथा ट्रक के परमिट सन् १९५३-५४ में इलाहाबाद से दिये गये ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—५२ जनभार वाहन परमिट, १४९ सार्वजनिक भार वाहन परमिट, ८४ निजभार वाहन परमिट।

तारांकित प्रश्न ७ व ८ के स्थगन पर आपत्ति

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, ७,८ नम्बर पर जो मेरे प्रश्न हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इनको एक महीने से स्थगित किया जा रहा है मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सीधे सादे थे।

श्री अध्यक्ष—यहां पर मैं जवाब नहीं दे सकता। आप मेरे कमरे में आ जायं तो मैं आपको बतला दूंगा कि इनको क्यों स्थगित किया गया।

१९५५-५६ का आय-व्ययक

श्री अध्यक्ष—अब माननीय वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष, १९५५-५६ ई० का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५५-५६ का बजट प्रस्तुत करता हूं :

२—दो साल हुए सन् १९५३-५४ का बजट उपस्थित करते हुए मैंने इस पर जोर दिया था कि सरकार का मकसद उत्तर प्रदेश को कल्याणकारी राज्य बनाना है। इस वर्ष हम अपने मक़सद में एक क़दम और आगे बढ़े हैं। कांग्रेस अवाडी सेशन म यह निश्चय किया गया कि भारत में सब सरकारें सोशलिस्ट प्रकार का समाज स्थापित करें। यह समाज ऐसा हो जिसमें उत्पादन के साधन या तो समाज की मिल्कियत हों या उसके नि त्रण में हों और उत्पादन तेजी के साथ किया जाये तथा धन का वितरण न्यायसंगत हो। इस उद्देश्य की पाबन्दी करने की हालत में प्लानिंग खर्च की गुंजाइश की नजर से नहीं बल्कि इस लिहाज से करनी पड़ेगी कि लोगों की आवश्यकतायें कितनी पूरी करनी हैं और इसलिये अब आर्थिक नीति में भी तब्दीली करनी होगी क्योंकि जो नीति अब तक रही वह कमी के समय के लिये उचित थी जब कि जरूरी चीजें प्राप्त नहीं होती थीं। लेकिन अब सूरत बदल जाने पर ऐसे ढंग अख़्त्यार करने होंगे जिनसे उत्पादन और जोर से बढ़े और उसका वितरण न्यायसंगत हो जिससे लोगों के जीवन का स्तर तेजी के साथ ऊंचा उठे। जो परिवर्त्तन अब हुआ है वह हमारी पालिसी में पहले से ही था। इसीलिये आप देखेंगे कि इस बजट में जो मैंने आज पेश किया है, कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें इस परिवर्त्तन की साफ़ झलक मौजूद है।

३—जब से देश आजाद हुआ केन्द्रीय और राज सरकारों द्वारा कांग्रेस एक प्लान के अनुसार देश की इकोनामी (Economy) के हर हिस्से में विकास कराती रही है।

पहली पंचवर्षीय योजना सन् १९५१–१९५६ के लिये बनाई गई। हमारे देश में यह अपने क़िस्म का पहला क़दम था जो उठाया गया। इससे पहले हमको प्लान बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था और देश की आर्थिक स्थिति ऐसी थी जिससे हिम्मत टूटती थी। ज़रूरी चीज़ें जैसे कपड़ा, खाना नहीं मिलते थे, आमतौर पर एक मुसीबत सी फैली हुई थी। सर्माया नहीं बनता था, उत्पादन गिर रहा था और रुपये की क़ीमत घटती जा रही थी। ख़र्च करने की जो पालिसी भी होती उस पर इन तमाम बातों का असर होना आवश्यक था। इसलिये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यह रक्खा गया कि खाद्य के मामले में हम अपना बोझा खुद सम्हालने के क़ाबिल हो जायें, यातायात और विद्युत् को बढ़ाया जाय ताकि आइन्दा जो प्रोग्राम छोटे-बड़े उद्योग-धंधों के बढ़ाने के लिये बनाया जाय उसमें आसानी हो। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य अंग ऐसे काम हुए जैसे आबपाशी का बढ़ाना, कृषि और पशुपालन को उन्नति देना, बिजली घरों का बनाना तथा यातायात का फैलाना। जहां तक भी हो सका इन कामों पर विशेष ख़र्चा किया गया। इससे यह भी अंदाजा किया जा सकता है कि इस सूरत मे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन (Industrialization) और सोशल सर्विसेज़ को एक साथ लेने की गुंजाइश नहीं थी। नियोजन या प्लानिंग इसका नाम है कि किस काम को पहले रक्खा जाय और किसको बाद में। पंचवर्षीय योजना से जो नतीजे अब तक निकले हैं उनसे साबित होता है कि जो किया गया वही ठीक था बावजूद इसके कि अभी एक साल बाक़ी है फिर भी हमारा प्लान अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल हो चुका है। देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर (Self sufficient) हो चुका है। यह सफलता एक बड़ी सफलता है। ज़रूरी चीज़ों की क़ीमतें भी एक हद तक घटी हैं और जिन कारणों से रुपये की क़ीमत घट सकती है उनका भी ख़ात्मा हो चुका है। कन्ट्रोल बड़ी हद तक उठ चुके हैं, पूंजी बनना आरम्भ हो गया है, पब्लिक सेक्टर में करोड़ों रुपया पब्लिक के फ़ायदे के कामों पर ख़र्च हो चुका है, मुख्य चीज़ों का उत्पादन ४० से ५० फ़ीसदी तक बढ़ गया है और क़ीमतें आमतौर से १० फ़ीसदी घट गयी हैं। अब इस विषय में जो करना है वह केवल यह है कि क़ीमतों में गिराव माकूल सीमा से आगे न जाने पाये। आशा है कि पहली पंचवर्षीय योजना का काम समाप्त होने पर भविष्य की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिये एक अधिक अनुकूल या ज्यादा मुआफिक वातावरण उत्पन्न हो जायगा। इसके यह मानी होंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना अपने असल मक़सद में कामयाब हो गई और देश को अपनी इकोनामी (Economy) के नियोजन और उस के चलाने का कामयाब तजुर्बा हो गया। अब दुविधा भरोसे में बदल रही है। इन्तज़ामी भी और टेक्निकल जानकारी बढ़ रही है। सरकार के विकास के कामों में जनता का सहयोग भी बढ़ता जा रहा है। क्या यह सब बातें हम सबको अपनी सफलता पर गर्व करने की नहीं हैं? अगर लड़ाई जैसी कोई मुसीबत बीच में न आ पड़ी तो भरोसे के साथ यह आशा की जा सकती है कि देश की आर्थिक समृद्धि या ख़ुशहाली बराबर बढ़ती चली जायगी।

४—अपने देश के इतिहास के सब से अधिक महत्वपूर्ण समय में हिम्मत कायम रखने के लिए हमको यह बात बार-बार याद करनी चाहिए कि पहली ही कोशिश में जो सफलता हमने प्राप्त की है वह किसी भी पश्चिमी देश की सफलता से कम नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हममें बहुत से इस महत्वपूर्ण बात को, जो अभी कही गई है, भूल जाते हैं और अपने आप को बिला वजह उस ख़ुशी से महरूम करते हैं जो हरएक को देश के कारनामों पर होनी चाहिये। मेरी राय में यह बहुत आवश्यक है कि हम यह जानें कि विकास का क्या काम हुआ और इससे क्या फायदा पहुंचा। साथ ही साथ यह भी जानना चाहिए कि विकास का जो काम आगे चल कर करना है उसके लिये कितने त्याग की आवश्यकता है। हर एक को ख़्वाह वह कहीं का हो और किसी दर्जे का हो सरकार की उस कोशिश को, जो जीवन का स्तर उठाने की की जा रही है, अपनाना चाहिए और ख़ुशी के साथ वक़्त, जान और माल से देश की सहायता करनी चाहिए। जब तक लोग आमतौर पर देश के कारनामों को अपने ज़ाती

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम]

कारनामे समझ कर गर्व नहीं करेंगे विकास पूरी सरगर्मी के साथ नहीं हो सकता। अब मैं आप के चन्द मिनट यह बयान करने के लिये लेता हूं कि स्वतंत्रता आने के समय से अब तक उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ।

५—मैं सिंचाई से आरम्भ करता हूं। सिंचाई के जो बड़े डाम बन चुके हैं उनकी एक लम्बी और शानदार फेह रिस्त है। नगवा, ललितपुर, सपरार, खजुरी, हिमइया, कबरई, रनगंवा, अहरौरा डाम तथा बेलन कैनाल वेयर बन कर तैयार हो चुके हैं जिनसे सिंचाई होती है। चन्द्रप्रभा, अर्जुन, माताटीला, नौगढ़ और सिरसी बांध तथा टोंस कैनाल प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जो थोड़े दिनों में समाप्त हो जायगा। इनके अतिरिक्त चन्द और भी काम हैं जो समाप्त होने वाले हैं। रिहन्द बांध का काम भी हाथ में ले लिया गया है जिससे २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस पर व्यय करने के लिये ६ करोड़ रुपया बजट वर्ष में रक्खा गया है। ३,००० से अधिक नये ट्यूबवेल्स और ४९,००० से ज्यादा पक्के कुएं बन कर पानी देने लगे हैं। इनके अतिरिक्त ३,२०० मील नई नहरों की शाखें बन चुकीं जिनसे २८,००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। २९,००,००० एकड़ बंजर जमीन जोत में आ गई और ग़ल्ले की पैदावार ७,००,००० टन सालाना बढ़ गई। इस सबका परिणाम यह हुआ कि खाद्य का मसला हल हो गया जिस पर बजातौर पर गर्व किया जा सकता है। इसके दूसरे माने यह भी होते हैं कि सरकार ने इन्डस्ट्रियलाइजेशन और सामाजिक कल्याण के लिये ठोस बुनियादें स्थापित कर दी हैं।

६—अब विद्युत् शक्ति को लीजिये जो इन्डस्ट्रियलाइजेशन की दूसरी आवश्यकता है। इसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो काम हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश की सूरत बदलती जा रही है। पिछले ७ (सात) साल में सरकारी बिजली घरों द्वारा ६९,५२४ किलोवाट का इजाफा हुआ। कितनी ही जगहों में बिजली लग चुकी है, और साल ब साल गांवों और कस्बों में लगती जा रही है। अब तक जो कुछ हुआ उसकी बिना पर यकीन किया जा सकता है कि उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए बिजली का पूरा प्रबन्ध हो जायगा। उद्योग-धन्धों की खातिर यातायात की तरफ भी ध्यान दिया गया। इसका प्रबन्ध हो रहा है। और सड़कों का तो इस राज में एक जाल ही फैल गया है इनके लिए जितना खर्चा पहले पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया था, हम उससे अधिक खर्च कर चुके। ३,९०९ मील पक्की और ५,२५९ मील कच्ची सड़कें बन चुकी हैं। बड़ी इन्डस्ट्री के क्षेत्र में जो पहला काम राज स कार ने हाथ में लिया था, वह हो चुका। मेरा मतलब गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी से है जो पांच महीने से सीमेंट बना रही है जिसकी मात्रा अब ७०० टन रोजाना हो गयी है। गवर्नमेंट प्रेशीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी तक़रीबन १०,००० वाटर मीटर (Water Metres) सालाना बना रही है जिसका उत्पादन और बढ़ने की आशा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट फैक्टरी ा उत्पादन और बढ़ानें का इरादा है और इसकी भी आशा है कि कोई और बड़ी इन्डस्ट्री भी स्थापित की जाय। यह याद रखना चाहिए कि भारी इन्डस्ट्री स्थापित करने में केवल बहुत खर्चा ही नहीं लगता, बल्कि बहुत समय की भी आवश्यकता होती है। चूंकि मौजूदा परिस्थिति में उत्पादन और रोजगार के साधन बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए छोटे और घरेलू उद्योग-धन्धे भी, जिनमें पूंजी कम लगती है, बढ़ाने की भी कोशिश की गयी। कितनी ही योजनायें ऐसी जारी की गयीं, जिनसे घरेलू उद्योग-धन्धों के लिए कच्चा माल और टेक्निकल शिक्षा मिले। उनकी Quality ठीक हो और उनके बिक्री का प्रबन्ध हो। हैन्डलूम की बनी हुई चीजों, रेशमी सामानों, चमड़े की रंगाई, ऊनी माल की तैयारी, ताले, छुरी-कांटे, खेल-कूद का सामान और ऐसी ही दूसरी चीजों के लिए विशेष योजनायें एक करोड़ सालाना से ज्यादा खर्चे पर चल रही हैं और अगले चन्द वर्षों में इससे भी अधिक करना है। इन धन्धों के रास्ते में एक खास अड़चन रुपये की आती है इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट फाइनेंशल कारपोरेशन (State Financial Corporation) स्थापित कर दिया है। इसका प्रास्पेक्टस (Prospectus) जारी हो चुका है, और यकीन है कि अगले एक दो महीनों में छोटे उद्योग-धन्धों को क़र्जा मिलने लगेगा।

७—मैंने अब तक ऐसे सामानों का चर्चा किया जिनकी आवश्यकता मैटीरियल प्रोडक्शन (Material Production) के लिये होती है। मगर इनके अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं तथा सामाजिक संस्थाओं के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ किया जा चुका है—जैसे काश्तकारों में आर्थिक प्रोत्साहन लाने के लिये जमींदारी की पुरानी प्रथा का विनाश, गांव वालों को अपनी मदद स्वयं करने के योग्य बनाने के लिये पंचायत राज्य की स्थापना और गांव के पूर्ण क्षेत्र को अपने आंचल में लेने के लिये हजारों सहकारी समितियां कायम करना। यही नहीं, बल्कि चकबंदी भी आरम्भ की गयी और करोड़ों रुपए के खर्च पर ऐसी योजनायें चालू की गयीं, जिनसे लेबर का कल्याण हो, इसके लिये घर बनें कर्मचारियों के लिए बीमा करने का प्रबन्ध हो, बेरोजगारी मिटे, लोग बाढ़ से बचें और अपनी मदद आप करें। हजारों स्कूल, कालेज और दूसरी शिक्षा की संस्थायें सैकड़ों चिकित्सालय और शफाखाने खोले जा चुके हैं। इसी बजट में मेडिकल और पब्लिक हेल्थ विभाग को पहले से ५६ लाख रुपया अधिक दिया जा रहा है। कमजोरों और विधवाओं के घर, अनाथालय यानी यतीमखाने, लेबर के आराम घर, बच्चों के पार्क, खेलों के मैदान और जच्चा-बच्चाखाने वगैरह भी स्थापित किये जा रहे हैं। सामाजिक कल्याण के लिए एक नया विभाग भी खोला गया जो शायद देश भर में अपने प्रकार का पहला विभाग है। आर्थिक विषमता यानी नाबराबरी कम करने के लिए ऐसे काम किए गए जैसे लेबर की मजदूरी को रहन-सहन के खर्चे से संबंधित करना, काश्तकारों के साथ काम करने वाले लेबर की मजदूरी मुकर्रर करना और कम तनख्वाह वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता बढ़ाना। हरिजनों और पिछड़ी हुयी जातियों को अपना सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उठाने में सुविधायें देने के लिए बहुत रुपया व्यय किया जा रहा है। बजट वर्ष में हरिजन सहायक विभाग का खर्चा ७४ लाख पर पहुंच रहा है जो कभी ६ लाख था। इन्तजामी क्षेत्र में अमनो-अमान की स्थिति मजबूती के साथ बेहतर हो रही है। ऐसे भी कदम उठाये गये जिनसे पुलिस के कर्मचारियों का मोरेल (Morale) ऊंचा हो और गांवों के रहने वालों में सुरक्षा यानी हिफाजती समितियां तथा वालन्टियर संस्थायें स्थापित करने का उत्साह पैदा हो। चुनांचे ऐसी समितियां बहुत से जिलों में बन गयी हैं अदालती और इन्तजामी अधिकारों को भी पृथक् यानी जुदा किया गया। हमारी जेलों की व्यवस्था या निजाम की एक अंतर्देशीय विशेषज्ञ यानी इन्टरनेशनल इक्सपर्ट ने इन शब्दों में तारीफ की है कि यह निजाम सारे एशिया में बेहतर है। सरकार के इन्तजाम में इफीशियन्सी (Efficiency) बढ़ाने और खर्चे में कमी करने के लिए भी विशेष कदम उठाये गये हैं। देहाती क्षेत्रों में नलों द्वारा पीने के पानी और बिजली की योजनायें जारी की गयीं।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल इक्सटेन्शन सर्विस योजनायें उत्तर प्रदेश के एक चौथाई गांवों में चालू हो चुकी हैं। इन स्कीमों के मातहत कृषि, पशुधन, सिंचाई, सफाई, इलाज की सुविधायें, शिक्षा और सहकारी समितियों वगैरह का विशेष काम हो रहा है। खुलासा यह है कि गांव वालों में उत्साह पैदा करके उनके जीवन के स्तर को उठाया जा रहा है। कोई देखना चाहे तो उसको यह दिखायी देगा कि आंखों के सामने देहात की जिन्दगी के लिए एक उम्मीदों भरा इंकलाब है।

८—जो कुछ अब तक निवेदन किया गया उससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट प्रकार के कल्याणकारी राज का रूप हर साल निखरता चला जा रहा है। सरकार का यह पक्का इरादा है कि अगली पंचवर्षीय योजना ऐसी हो जिससे यह निखार और बढ़े और समाज में ऐसी खुशहाली पैदा हो जिसकी बुनियाद न्याय, स्वतंत्रता और बराबरी पर कायम हो।

९—अब मैं इस पर आता हूं कि इस विकास का परिणाम क्या है। इसका रूप उस खर्चे के दर्पण में नजर आता है जो राजस्व और ऋण से हो रहा है। सन् ४५–४६ में राजस्व लेखे से विकास पर १२,३२,००,००० रुपया व्यय हुआ जबकि ५०–५१ में

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

२५,३०,००,०००, और ५२-५३ में २८ करोड़, सन् ५४-५५ में यह खर्चा ३७,०६,००,००० तक पहुंचता दिखायी देता है। इस बजट में इसके लिए ४४,७६,००,००० रुपया रक्खा गया है। सन् ४५–४६ में विकास पर कैपिटल एकाउन्ट यानी पूंजी लेखे से सिर्फ १,५४,००,००० रुपये खर्च हुए थे जबकि इस बजट में इस लेखे से व्यय करने के लिए ३५,७१,००,००० रुपये रक्खे गए हैं। इसके अलावा बजट वर्ष में ११,०६,००,००० रुपया लोकल बाडीज़ को कर्ज़ दिया जाने वाला है जो उनके ज़रिए से विकास पर खर्च होगा। इस तरह बजट वर्ष में राजस्व, पूंजी और ऋण से कुल ९१,५३,००,००० रुपया व्यय होने वाला है। यह ऐसी रक़म है जिसकी चन्द साल पहले कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

१०—इसका खुला नतीजा यह है कि जब तक खर्चे के साथ-साथ सरकार की आमदनी भी न बढ़े उस वक्त तक इस तेज़ी के साथ विकास का काम नहीं किया जा सकता। इसकी मुश्किल से आशा की जा सकती है कि इतने बड़े खर्चे का कोई भी माकूल हिस्सा राजस्व से आये। इसलिये यह बात माननी पड़ेगी कि भविष्य में उत्तर प्रदेश का कर्ज़ा विकास के खर्चे के मुताबिक बढ़ेगा और हमको न केवल विकास के नए खर्चे के लिए बल्कि पहले लिये हुये क़र्ज़े के वास्ते भी ऋण पर निर्भर होना पड़ेगा। यहां हमको यह भी जान लेना चाहिए कि इस बजट में जितना खर्चा विकास के लिए रक्खा गया है आइन्दा के लिए उतना भी काफी नहीं होगा और अगर हम उस लक्ष्य (Target) को प्राप्त करना चाहें जो लोगों की ज़रूरतों को देखकर दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए रक्खा जायगा और जिस तक हमको ज़रूर पहुंचना पड़ेगा तो यह खर्चा और भी बहुत बढ़ेगा। राज्य सरकार को भरोसा है कि जो खर्चा बढ़ेगा उसका बहुत हिस्सा ग्रांट और ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार से मिल सकेगा लेकिन इसी के साथ यह भी है कि यहां के रहने वालों को भी अब से अधिक इसका बोझ सहना और सहयोग देना होगा ताकि आने वाले विकास के खर्चे की पूर्ति हो सके।

११—यहां इस पर ज़ोर देना चाहता हूं कि इस बजट में विकास के लिए जो रुपया रक्खा गया है वह उस त्याग का पता देता है जो हम सबको पब्लिक के फायदे के लिये करना है। विकास के प्रोग्राम के बढ़ने के मानी यह हैं कि लोग सरकार को ज्यादा रुपया दें, ख्वाह वह टैक्स की शक्ल में हो या क़र्ज़े की बराहेरास्त दिया जाय या डिफिसिट फानेंन्सिग (Deficit Financing) के परिणाम में। इसको यों भी कह सकते हैं कि कल की बेहतरी के लिए आज तकलीफ उठानी ज़रूरी है। जीवन का स्तर बगैर वास्तविक धन पैदा किये हुए नहीं उठाया जा सकता और वास्तविक धन कठिनाई सहकर ठोस काम किए बगैर पैदा नहीं हो सकता। मुझे कोई शंका नहीं है कि लोग इसको समझेंगे और उस तकलीफ को बरदाश्त करेंगे जो भविष्य में रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने के लिए आवश्यक है। मैं अपील करता हूं कि लोग अपनी आय का ज्यादा से ज्यादा सम्भव भाग नेशनल लोन, सेविंग्स सर्टीफिकेट और बचत की अन्य योजनाओं में लगायें। मैं यह भी अपील करता हूं कि श्रमदान से मदद की जाय और टैक्स वक्त पर और पूरे तौर पर अदा किया जाय। राज सरकार के सामने जो कार्य है वह यह है कि टैक्स, ऋण डेफिसिट फायनेंसिग (Deficit Financing) और पब्लिक व्यय का ठीक-ठीक उपयोग करके खुशहाली लाने वाले साधन पैदा करे ताकि उत्पादन बढ़े और धन का वितरण यक़ीनीतौर पर न्याय-संगत हो। परन्तु यह काम जभी हो सकता है जबकि लोग उन तदबीरों की आवश्यकता को समझें जो अख्तयार की जायेंगी और उनके अनुसार जो कुछ किया जाय उसमें अस्थायी कष्ट होने के बावजूद हृदय से पूर्ण सहयोग दें। अगर लोगों ने ऐसा किया तो मैं बगैर किसी दुविधा के यक़ीन दिलाता हूं कि रुपए की कमी के कारण तेज़ से तेज़ रफ्तार पर विकास करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आयेगी।

१२—अब मैं सदन के सामने बजट के वह आंकड़े पेश करूंगा जिनमें सरकार की १९५३–५४ की वाकई आय और व्यय, १९५४–५५ के दुहराये हुए और १९५५–५६ के बजट तखमीने बताये गये हैं।

१३—नीचे दिये हुए नक्शे में १९५३-५४ के लेखे संक्षेप में दिये गये हैं :—

(लाख रुपयों में)

	मूल बजट	वास्तविक आंकड़े
आरम्भिक शेष (Opening balance)	(Original budget) १,९५	(Actuals) ७,५६
१—संचित निधि (Consolidated Fund)—		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Head)—		
(१) प्राप्तियां (Receipts) ..	७४,३८	७५,६४
(२) व्यय (Charges) ..	७८,८०	७२,८१
	-४,४२	+२,८३
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure)	७,०९	७,४६
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from public loans)	+३,००	+५,४१
(घ) दूसरे ऋणों और जमा शीर्षक (शुद्ध) [other debts and deposit heads (net)]	+६,२६	+१०,९५
२—आकस्मिकता व्यय निधि [contingency fund]	..	-११
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account (net)]	+१,६६	-३,५२
इस वर्ष में हुए सभी लेन देन का शुद्ध फल (Net result of all the transactions in the year)	-५९	+८,१०
अन्तिम शेष (closing balance)	१,३६	१५,६६

१४—मुख्यतया बकायों की वसूली होने के कारण मालगुजारी की प्राप्तियों और लगान की उगाहियों में १७२ लाख रुपये की बढ़ती हुई और गन्ना उपकर (Sugarcane cess) से होने वाली प्राप्तियों में २१६ लाख रुपये की वृद्धि हुई। आय-कर (Income tax) से मिलने वाले राज्य के भाग में भी ४० लाख रुपये की बढ़ती हुई। इसके मुकाबले में सिंचाई से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों (net irrigation receipts) में २३६ लाख रुपये की कमी हुई, क्योंकि मूल बजट में सिंचाई की दरों के दुहराये जाने से पूरे साल की अतिरिक्त प्राप्तियों का हिसाब लगाया गया था जब कि सिर्फ खरीफ की देय धनराशियों (dues) के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्राप्तियां वसूल की गई थीं। ऋण सम्बन्धी व्ययों (debt charges) में ४९७ लाख रुपये की कमी हुई जिसका मुख्य कारण प्रतिकर और पुनर्वास सम्बन्धी अनुदानों के बांडों (Compensation and Rehabilitation Grant Bonds) का जारी न किया जाना था। मालगुजारी (Land Revenue) के व्यय में भी ९७ लाख रुपये की कमी हुई जो मुख्यतया गांव स्तर पर भूमि व्यवस्था के कर्मचारियों (Land Records staff) के पुनस्संगठन के फलस्वरूप हुई और इसका कारण यह भी था कि निबंधन और प्रतिकर (Assign-

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

ments and Compensation) के लिए निर्धारित की हुई रकमों को पूरा-पूरा काम में नहीं लाया जा सका। गवर्नमेंट रोडवेज पर होने वाले व्यय में भी ७८ लाख रुपये की कमी मुख्यतया इसलिए हुई कि कानूनी कठिनाइयों के कारण कुछ नये रूटों के अधिकार में लिये जाने में देरी हुई। लेकिन यांत्रिक खेती (Power cultivation) और उपनिवेशन योजनाओं (Colonization Schemes) पर होने वाले व्यय में १४४ लाख रुपये की बढ़ती हुई जो मुख्यतया दायित्वों (liabilities) को जिनमें सेंट्रल ट्रेक्टर आर्गेनाइजेशन को अदा किया हुआ जमीन तोड़ने का व्यय भी शामिल था देर से समायोजन (adjustment) करने के फलस्वरूप हुई। ऊपर दी हुई और दूसरी कमियों और बढ़तियों से पहले जो ४४२ लाख रुपये की कमी होने की उम्मीद की गई थी वह २८३ लाख रुपये की बचत में बदल गई।

१५—नीचे लिखे हुये अंक (figures) चालू मालयाती साल के दुहराये हुए तखमीनों को संक्षेप में दिखाते हैं :—

(लाख रुपयों में)

	मूल बजट (Original budget)	दुहराये गये तखमीने (Revised)
आरम्भिक शेष (Opening balnce) ..	२,३३,	१५,६६,
१—संचित निधि (Consolidated fund)—		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)—		
(१) प्राप्तियां (Receipts) ..	७७,१६,	७९,५६,
(२) व्यय (Charges) ..	८१,०७,	७९,५६,
	– ३,९१	..
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure)	२०,२२,	१४,९६,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net receipts from public loans)	+६,००,	..
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debt and deposit heads (Net)]	+२०,०१,	+१४,३०,
२—आकस्मिकता व्यय निधि (Contingency fund)	..	+२
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account (net)]	–२,५६,	–१३,६२,
इस वर्ष में हुये सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all the transactions in the year)	–६८,	–१४,२६,
अंतिम शेष (closing balance)	१,६५,	१,४०,

१६—मालगुजारी (Land Revenue) में १०४ लाख रुपये की बढ़ती होने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि कागजातदेही (Land Records) की दुरुस्ती होने से अच्छी उगाहियां (Collections) और अतिरिक्त प्राप्तियां (additional receipts) हुई हैं। सिंचाई से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों (Net irrigation receipts)

में ७६ लाख रुपये की कमी जाहिर होती है और गांव सभाओं और पंचायतों के चुनावों को मुल्तवी करने से ७० लाख रुपये की कमी होगी। खर्चे की तरफ विकास संबंधी स्थानीय निर्माण कार्यों (local development works) को करने से जिनके लिये भारत सरकार से राज-सहायता मिलती है, १०५ लाख रुपये की बढ़ती की उम्मीद की जाती है। चूंकि इस साल कम रकम के प्रतिकर बांडों (Compensation bonds) के जारी किये जाने की उम्मीद है इसलिये ऋण संबंधी व्यय (Debt charges) में ३३० लाख रुपये की कमी होने की संभावना है। ऊपर बताई गई और दूसरी कमियों और बढ़तियों से कमी की रकम जिसकी मूल बजट में ३९१ लाख रुपये की होने की उम्मीद की गई थी अब इससे घटकर २२१ लाख रुपये रह जाने की उम्मीद है। यह रकम राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) से इतनी ही धनराशि लेकर पूरी कर दी जायगी। पूंजी व्यय (Capital expenditure) में अधिकांश कमी का कारण बिजली के निर्माण कार्यों की योजनाओं में कम प्रगति होना है क्योंकि मुख्यतया प्लांट और साज-सज्जा (Equipment) की सप्लाई में देरी हुई है। ६०० लाख रुपये का प्रस्तावित सरकारी ऋण नहीं लिया गया है क्योंकि केंद्रीय सरकार द्वारा नेशनल प्लान लोन लिया गया है जिसमें से केवल ३०० लाख रुपये की रकम राज्य सरकार के लिये नियत की गई है।

१७—नीचे दी हुई तालिका (table) में बजट के तखमीने संक्षेप में दिखाये गये हैं :—

	(लाख रुपयों में)
आरम्भिक शेष (Opening balance)	१,४०,
१—संचित निधि (Consolidated Fund)—	
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Head)—	
(१) प्राप्तियां (Receipts)	८४,५६,
(२) व्यय (Charges) ..	९०,०६,
	– ५,५०,
(ख) पूंजी व्यय (Capital expenditure) ..	३२,७०,
(ग) सार्वजनिक ऋण से शुद्ध प्राप्तियां (Net Receipts from Public loans) ..	+६,००,
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debt and deposits head (net)] ..	+२२,३३,
२—आकस्मिक व्यय निधि (Contingency Fund) ..	..
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public account (net)] ..	+९,३६,
इस वर्ष में हुये सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all the transactions in the year)	–५१
अंतिम शेष (closing balance)	८९,

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

१८—बजट वर्ष में मालगुजारी से होने वाली प्राप्तियों और सिंचाई से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों में कुल मिलाकर २७१ लाख रुपये की बढ़ती होने की संभावना है। गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री से होने वाली आय में १३७ लाख रुपये की बढ़ती होने की उम्मीद की जाती है। संघीय उत्पादन शुल्कों (Union Excise Duties) और सम्पत्ति कर (Estate duty) से इस सरकार को मिलने वाले भाग में ६० लाख रुपये की अतिरिक्त रकम की आशा की जाती है। दूसरी तरफ बजट वर्ष में आय कर (Income tax) से राज्य सरकारों को मिलने वाले भाग में ७५ लाख रुपये की कमी होने की संभावना है। बजट के तखमीनों में सामुदायिक योजनाओं (Community Projects) और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना (National Extension Service Scheme) के खर्चे में ३२९ लाख रुपये, उद्योग विभाग के खर्चे में १५४ लाख रुपये, मालगुजारी के खर्चे में ६७ लाख रुपये, शिक्षा के खर्चे में ७४ लाख रुपये, चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य (Medical and Public Health) के खर्चे में ५६ लाख रुपये, पुलिस के खर्चे में ५५ लाख रुपये, कृषि संबंधी इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (Agricultural Engineering and Colonization) के खर्चे में ४५ लाख रुपये और परिवहन (Transport) के खर्चे में ३१ लाख रुपये की बढ़ती जाहिर होती है। इन बढ़तियों के मुकाबले में विविध और असाधारण व्यय (Miscellaneous and Extraordinary charges) में ३३८ लाख रुपये की कमी जाहिर होती है। इन और दूसरी बढ़तियों और कमियों का शुद्ध (net) फल यह है कि इनसे राजस्व में ५५० लाख रुपये की कमी होने की संभावना है। इस बात का ख्याल रखते हुए कि एफीशेंसी (Efficiency) पर कोई असर न पड़े, इस कमी को जिस कदर भी पूरा किया जा सकता है हर किस्म की फिजूल खर्ची मिटाकर पूरा किया जायेगा। मेम्बरान जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस काम के लिये एक कमेटी बिठा रक्खी है जिसमें दोनों सदनों के मेम्बरान और दूसरे साहबान सम्मिलित हैं, ताकि खर्चे में ऐसी कमी की जाये जिसका असर मुफीद कामों के खर्च पर न पड़े। यह कमेटी पूरे खर्च को इस नजर से जांच रही है कि मकसद हासिल हो जाये। मैं इस सदन को यकीन दिलाता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने पर गवर्नमेंट उस पर पूरे तौर पर विचार करेगी जिस हद तक यह कमी अपने साधनों को बढ़ाकर या किफायत कर के पूरी नहीं की जा सकती उस हद तक इसको पूरा करने के लिये बजट वर्ष में भी राजस्व सुरक्षित निधि (Revenue Reserve Fund) से रुपया निकालना पड़ेगा।

१९—मैंने अब तक जो कुछ निवेदन किया उसमें विकास के बाबत भी कहा मगर अब मैं यह चाहता हूं कि विकास के सम्बन्ध में यह दिखाऊं कि जो कुछ पहले हो चुका है उसके अतिरिक्त चालू वर्ष के अन्दर और क्या हो जायेगा और जो रुपया सन् १९५५–५६ के लिए बजट में रक्खा गया है उससे क्या होगा। यह जाहिर है कि बजट स्पीच में उन तमाम कामों का ब्योरा नहीं दिया जा सकता जो किसी साल के अन्दर कर दिये गये हों या किसी साल में किये जाने वाले हों। उनमें से बाज ही दिखाये जा सकते हैं। इसकी भी आवश्यकता हो सकती है कि किसी ऐसी बात को जो पहले कह चुका हूं अगले बयान में किसी जगह या जगहों पर दोहराना पड़े। गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वह विभागों द्वारा होते हैं, इसलिये अब कुछ देर तक मैं जो कुछ कहूंगा वह विभागों के सम्बन्ध में होगा। पहले कृषि और पशुपालन से आरम्भ करता हूं।

कृषि और पशुपालन

२०—जब यह कहा गया कि खाद्य का मसला हल हो गया तो उसका मतलब यह था कि उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिये उत्तर प्रदेश में गल्ले की पैदावार काफी हो गई बल्कि उत्तर प्रदेश इस योग्य भी हो गया कि देश में कहीं और जरूरत हो तो किसी हद तक

मदद भी कर सकता है। चुनांचे गेहूं और चावल यहां से बाहर भेजे भी गए। यहां केवल यही नहीं किया गया कि नई ज़मीनें काश्त में लाई गईं बल्कि जिन ज़मीनों में खेती होती थी उनकी पैदावार भी सिंचाई, खाद और उम्दा बीज दे कर बढ़ाई गई। कृषि विभाग द्वारा गेहूं, चना, जौ, मटर, आलू, गन्ना, धान, ज्वार, मकई और बाजरे की नई किस्में भी बुवाई गईं, जो रोगों का ख़ूब मुक़ाबिला करती हैं और बहुत पैदावार देती हैं। फसलों की पैदावारों के मुक़ाबले भी इसलिये कराये जाते हैं कि काश्तकार एक दूसरे से ज्यादा ग़ल्ला पैदा करने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश के काश्तकारों ने गेहूं की पैदावार में पूरे भारत की पैदावारों से मुक़ाबिला किया और बुलन्दशहर के एक काश्तकार ने ६४ मन १२ सेर फी एकड़ की पैदावार दिखा कर कृषि पंडित का खिताब पाया। सन् १९४६–४७ में कुल फसली रक़बा ३,९९,८९,००० था जो मार्च सन् ५४ तक बढ़ कर ४,५०,६९,००० एकड़ हो गया।

कृषि की उन्नति के लिए पशुपालन भी बहुत आवश्यक है, उत्तर प्रदेश में इसकी ओर खास ध्यान दिया गया। अच्छे नस्लों के पशुओं की तादाद बढ़ाई गई ताकि अधिक दूध मिले और नस्लें बढ़ें। सन् १९५२–५३ में उम्दा नस्ल लेने की एक योजना बनाई गई और पहाड़ी जिलों में भेड़ और ऊन के विकास के लिये भी योजना बनी। इन योजनाओं में बड़ी कामयाबी हुई। जानवरों के इलाज के अस्पताल खोले गये जिनकी संख्या ४६–४७ में २०६ थी और चालू वर्ष के अन्त तक २५७ हो जायेगी। मार्च, सन् १९५५ तक ४७ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (Artificial Insemination Centre) हो जायेंगे। फसलों को तबाही से बचाने के लिये चालू वर्ष में एक नई स्कीम जंगली गायों को पकड़ने की चलाई गई। एक फार्म अल्मोड़ा के जिले में भेड़ों की नस्ल लेने का खोला गया। सीरा और वैक्सीन की बहुत मांग हो गई है। उसको पूरा करने के लिये Biological Products Section को और बढ़ाया जा रहा है। अगले वित्त वर्ष के प्रोग्राम में यह भी है कि जहां ज़रूरत हो वहां नये विटरिनियरी अस्पताल खोले जांय और पशु सुपरवाइज़रों के लिये ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाय। यह भी तजवीज़ किया गया है कि गैर-सरकारी आदमियों को मदद दे कर अच्छी नस्लों की गायों और भैंसों की तादाद के बढ़ाने का सिलसिला जारी किया जाय। मथुरा के विटरिनियरी कालेज में सन् १९५५–५६ में दाखिले की तादाद को १०० से बढ़ा कर १५० किया जा रहा है। सरकार ने सन् १९५३–५४ में एक गो-संवर्धन कमेटी बिठाई थी जिसके चेयरमैन डाक्टर सीताराम थे। यह इसलिये बैठाई गई थी कि पशुपालन के सम्बन्ध में तफ़सील के साथ तहक़ीकात कर के सिफारिशें करे। इस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी और सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया। यह बात अब से पहले सामने आ चुकी है कि इस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि गाय और इसकी नस्लों का कटना क़ानूनन बन्द किया जावे इसके लिये सरकार विधेयक (Bill) तैयार कराने वाली है।

सिंचाई

२१—चालू वर्ष में सिंचाई के रकबे में लगभग ७ लाख एकड़ की और बढ़ोत्तरी होने वाली है। बजट वर्ष में उन योजनाओं को समाप्त करने के अतिरिक्त जिन पर पहले से काम हो रहा है अन्य योजनाओं पर भी काम आरम्भ किया जायगा जिन्हें बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दिया जायेगा। इसी वर्ष में सत्रह सौ मील (१,७०० मील) नहरों की नयी शाखें तथा एक हजार (१,०००) नये ट्यूबवेल तैयार किये जायेंगे जिनके लिये रुपया रक्खा गया है। मार्च, सन् ५६ तक जबकि पहिली पंचवर्षीय योजना की अवधि खत्म होगी उत्तर प्रदेश में बाइस हजार आठ सौ (२२,८००) मील लम्बी नहरों की नयी शाखें और पांच हज़ार (५,०००) ट्यूब वेल हो जायेंगे। एक करोड़, चार लाख, चार हजार, पांच सौ (१,०४,०४,५००) एकड़ ऐसा रक़बा हो जायेगा जिसकी आबपाशी हो सकेगी।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

विद्युत् शक्ति

२२—चालू वर्ष में हरदुआ गंज बिजली घर में ७,००० किलोवाट का इजाफा हो चुका और जून, १९५५ तक पथरी और खटीमा Power Stations का कार्य पूर्ण हो चुकेगा जिनसे ४३,४०० किलोवाट बिजली मिलेगी। जिस रक़बे में 'शारदा' पावर स्टेशन की बिजली दी जायगी उसमें कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा। इस रक़बे में नैनीताल, अल्मोड़ा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई और लखनऊ के ज़िले सम्मिलित हैं। हरदुआ गंज और पथरी से Grid area में बिजली बढ़ेगी जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, एटा, बदायूं, रामपुर, देहरादून और टेहरी के ज़िले शामिल हैं। इस एरिया में घरेलू खर्च के लिये बिजली के मिलने पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा। और उद्योग-धंधों के लिये दस हार्स पावर तक हर शख्स को बिजली बगैर रुकावट मिल सकेगी और Cane Crusher के लिये पन्द्रह (१५) हार्स पावर तक, इससे ऊपर कन्ट्रोल रहेगा। दरख्वास्तों के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने नोटीफिकेशन (Notification) कर दिया था चुनांचे दरख्वास्तें आ रही हैं। विशेष तौर पर चर्चा करने के काबिल रिहंड डैम Power Project, पथरी पावर हाउस, गंगा तथा शारदा ग्रिड की नयी लाइनें, नहरों पर १४ पंपिंग स्टेशन्स, मऊ, गोरखपुर, सोहावल और मैनपुरी के स्थानों पर स्टीम स्टेशन हैं। बेकारी दूर करने के सिलसिले में प्रदेश के ३६ नगरों में बिजली देने की योजना भी है। पंचवर्षीय योजना का जो काम बिजली के मुताल्लिक था वह भी मार्च, सन् ५६ तक समाप्त हो जायेगा। इस सिलसिले में मैं थोड़ा-सा चर्चा Kanpur Electric Supply Undertaking का भी करना चाहता हूं जिसको कि सरकार ने १९४७ से अपने हाथ में लिया। उस समय इस कम्पनी में केवल १४,४०,००,००० यूनिट सालाना बिजली पैदा की जाती थी लेकिन मौजूदा साल के अन्त तक २१,००,००,००० यूनिट बिजली पैदा की जायेगी। अगले वर्ष इस कम्पनी से इतनी बिजली पैदा हो जायेगी कि घरेलू काम और उद्योग-धंधों के लिये बिना किसी कन्ट्रोल के कानपुर में बिजली मिल सकेगी।

सड़कें और यातायात

२३-(अ) सड़कें--हम सबको याद है कि सन् ४६ में उत्तर प्रदेश ने सड़कों का एक प्रोग्राम बनाया था, उसके और पंचवर्षीय योजना के मातहत इस राज्य में सन् ४६ से मार्च सन् ५४ तक ३,९०९ मील पक्की और ५,२५९ मील कच्ची सड़कें बनीं। १,७०० मील टार की गयी और २०८ मील सीमेंट ट्रैक बने। चालू वर्ष के आखीर तक २६० मील नयी पक्की सड़कें, १३९ मील सी० सी० ट्रैक बन जायंगी तथा ९२ मील फिर से बनेंगी। बजट वर्ष में करने के लिए जो काम रक्खा गया है, वह यह है कि ५५९ मील नयी पक्की सड़कें बनेंगी, १५५ मील का Tarring हो जायेगा तथा ३३ मील सड़कें दुबारा बनेंगी। सड़कों के बनाने के साथ-साथ वह सब पुल जो सौ फिट से कम चौड़े थे बनाये गये। सौ फिट और सौ फिट से ऊपर के पुल अब तक बीस (२०) बनाये जा चुके हैं जो पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं और यह आशा की जाती है कि मार्च, सन् ५५ तक बारह (१२) और तैयार हो जायेंगे। उन्तीस (२९) नये पुलों पर अगले साल काम आरम्भ होगा।

(ब) यातायात—यातायात का राज्य सरकार ने सन् ४७ में राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) किया। उस समय से बराबर हर साल सड़कें ली जा रही हैं और काम बढ़ाया जा रहा है। मार्च, सन् ५३ तक पांच हजार दो सौ उन्नीस (५,२१९) मील सड़कें ली जा चुकी थीं। यातायात के नेशनलाइजेशन (Nationalisation) की स्कीम पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल है। इस योजना के अन्त तक छः हजार पांच सौ (६,५००) मील नेशनलाइज़ हो जायेंगे जिन पर एक हजार पांच सौ (१,५००) बसें चलती होंगी। गवर्नमेंट ने यह निश्चय किया है कि यातायात के विभाग को स्थायी कर दिया जाये। [illegible]ट वर्ष में सोलह सौ (१,६००)

मुलाजिमीन स्थायी किये जायेंगे, बसें और वर्कशाप के लिए औजार तथा मशीनें खरीदी जायेंगी, बस-स्टेशन और बनेंगे और चूंकि बसें डेजिल आइल से चलायी जाने वाली हैं उनकी मरम्मत और देखभाल के लिए ट्रेनिंग भी दी जायगी।

गढ़वाल के रकबे में चौकसी करने के लिए कोटद्वार पर एक हिफ़ाजती दस्ता (Enforcement Squad) रक्खा जायगा।

उद्योग धन्धों का विकास

२४—इंडस्ट्री के विकास के लिये सरकार ने जो कुछ किया है उसके सम्बन्ध में मैं इस स्पीच के प्रारम्भ में कह चुका हूं। यह भी बतला चुका हूं कि सरकार ने एक प्रेसीजेन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी और सीमेंट फैक्टरी स्थापित की हैं। अब इतना और कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी पिछले चन्द वर्षों में कितनी ही नयी इंडस्ट्रीज बढ़ गयी हैं। यह बढ़ोत्तरी इसलिये हुई कि सरकार ने भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रोत्साहन दिया।

जो नयी industries उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई हैं, उनमें से चन्द यह हैं :—

हरीकेन लालटेनें, रेगमाल (sand paper), बटन, कार्बन पेपर, ट्यूबवैल के सामान अलम्यूनियम की चीजें, टूथ ब्रश, छापने की रोशनाई, लकड़ी के पेंच, टार्च, वेट-बैट्रीज (Wet Batteries), सर्जरी के औजार, शफाखानों में इस्तेमाल होने वाली चीजें, रबर, Conduct pipes, पेन्ट्स (Paints) और वार्निश, सोने के तार और दूसरी तरह के केमिकल्स (Chemicals) जैसे Sodium Sulphide और Sodium Silicate, इन नये धन्धों ने इस प्रदेश का रंग बदल दिया है। रोजगार के अवसर पैदा कर दिये हैं और State Dividend यानी राजधन को बढ़ने में मदद दी है। यही नहीं कि नये धन्धे बढ़ाये, बल्कि सन् ४६ से पहले से जो धन्धे यहां होते थे, उनकी उन्नति की ओर भी ध्यान दिया गया, मसलन सूती सामान, दफ्ती, प्लाईउड, रबर और चमड़ों के बेल्ट (Belt), तेल निकालने की मशीनें, कोल्हू, आटे की चक्की, Cold storage, फलों के मुरब्बे, केमिकल्स (Chemicals), अंग्रेजी दवासाजी, Essential oil, सरेस, प्लास्टिक, नल और सेनेटरी फिटिंग्स (Sanitary fittings), रेडियो असेम्ब्लेज (Radio Assemblage), फाउन्टेनपेन के पार्ट्स, कन्फेक्शनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, Electro plating और वेल्डिंग। इनमें उन्नति होने का यह परिणाम हुआ कि इनके कारखानों की संख्या सन् १९४६ ई० में नौ सौ इकहत्तर (९७१) थी, इससे बढ़ कर सन् १९५३ ई० में सत्तरह सौ तैंतालीस (१७४३) हो गई।

छोटे और घरेलू धन्धों के रास्ते में बाजार की कमी, उत्पादन का खर्चा, बरतने वालों का देशी चीजों के खिलाफ़ ख़याल, पूंजी और Know how यानी टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण जो रुकावट रही सरकार ने उसकी पूरी जानकारी रक्खी और उनके उत्पादन में सहायता करती रही और भिन्न-भिन्न यूनिटों और संस्थाओं के ज़रिये से इनकी पैदावार के वास्ते बाहर के बाजार तलाश करती रही। हेन्डलूम की हिफाजत और तरक्की के लिये जो स्कीम जारी की गई उसके द्वारा पचहत्तर (७५) उत्पादन सोसाइटियां, तीस (३०) रंगाई के घर (Dye Houses) और छप्पन (५६) डिपो हैन्डलूम माल की बिक्री बढ़ाने के लिये स्थापित किये गये। चमड़े की इन्डस्ट्री के लिये एक pilot project चालू किया गया है, जिससे आशा है कि वह आगरे के जूतों के काम की स्थिति को बेहतर और उसकी बुनियादों को मजबूत कर देगा। हैन्डलूम माल, छपाई, जूते, ताले, खेलों की चीजें, रेशम और ड्राइंग तथा सर्वे के औजारों के सम्बन्ध में Quality छाप योजना बहुत लाभदायक काम कर रही है। इसलिये इस योजना को बहुत हर-दिल-अजीजी हासिल हुई। घरेलू धन्धे वालों को अपना माल बेंचने में पहले जो कठिनाइयां मालूम होती थीं, उनमें कमी हो रही है। ऐसी तदबीरें भी अख्तियार की गई हैं जिनके कारण प्रदेश के अन्दर बनी हुई चीजें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बड़े पैमाने पर बाहर जा रही हैं। यह चीजें ऐसी हैं जैस जूट के थैले, कमाया-रंगाया हुआ चमड़ा, बनारस व टांडे की सिल्क, मथुरा, लखनऊ और फर्रुखाबाद के छपे हुये कपड़े, ताले, कैंचिया, ड्राइंग व सर्वे के औजार, खेलों के सामान, चूड़ियां, जूते, कालीन, साइकिलें व उनके पुर्जे, Brass ware, सींग की कंघियां और हैन्डलूम के बने हुये सामान।

शिक्षा

२५—जनतंत्र में शिक्षा का एक विशेष स्थान है। नागरिकों में पूरी जानकारी और समझ पैदा करने के लिये, जिससे वह अच्छे नागरिक बन सकें, शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिये यू० पी० सरकार का ध्यान इसकी ओर हमेशा बहुत आकर्षित रहा है। इस 'बजट' में खास शिक्षा अनुदान में १० करोड़ २१ लाख १८ हजार रुपया इस पर व्यय करने के लिये रक्खे गये हैं, जोकि चालू वर्ष के रुपये से लगभग ७४ लाख रुपया ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ४८ लाख ६१ हजार १०० सौ रुपया हरिजन विभाग में और ११ लाख ७१ हजार रुपया "रिलीफ रिहैबिलिटेशन" में इसी के लिये और रक्खे गये हैं। (इसके अतिरिक्त "टैक्नीकल" और "प्रोफेशनल", "एजुकेशन" के लिये, इस "बजट" में १ करोड़ ३६ लाख ९६ हजार १० रुपये भिन्न-भिन्न अनुदानों में रक्खे गये हैं। इस तरह हर प्रकार की शिक्षा पर व्यय होने के लिये जो रकम बजट में रक्खी गई वह इस बजट में १२ करोड़ १८ लाख ४६ हजार ११० रुपये हैं।

सन् १९४६ ई० के मुकाबिले में जबकि "बेसिक प्राइमरी स्कूलों" की संख्या १८ हजार थी, सन् १९५४ ई० में ३२ हजार हो गई और "हायर सेकेंड्री स्कूल" बढ़कर ३ हजार ७ सौ हो गये। शिक्षा को "साइंटिफिक" बुनियादों पर कायम करने के लिये इन स्कूलों में भिन्न-भिन्न पढ़ाइयों का इन्तजाम किया गया। सन् १९४७ ई० से सन् १९५४ ई० तक जो वक्त गुजरा, उसमें खास "स्कीमें" जारी की गई और खास "इन्स्टीट्यूशन्स" बनाये गये। उनमें से "ब्यूरो आफ साइकोलाजी", "गवर्नमेंट सेंट्रल पैडागौजिकल इन्स्टीट्यूट" और "Constructive ट्रेनिंग कालेज" खास तौर पर काबिले जिक्र है।

चालू वर्ष में जो काम हुआ वह शिक्षा की आइन्दा होने वाली उन्नति का पता देता है। इस वर्ष में जो खास बात की गई वह यह है कि "प्राइमरी" शिक्षा के साथ कृषि और दस्तकारी को लगाकर शिक्षा और जीवन में संबंध पैदा किया गया और इसका भी प्रबन्ध किया गया कि "टीचर" ऐसे हों जो "बेसिक" शिक्षा के उन्नति पाये हुये तरीकों से वाकिफ हों। केंद्रीय सरकार ने पढ़े-लिखे बेरोजगारों की मदद के लिये जो "स्कीम" बनाई थी, उससे फायदा उठाकर "जूनियर हाई स्कूलों" में दस्तकारी के कामों के केंद्र बना दिये गये। "सेकेंड्री एजुकेशन" में भी श्री नरेंद्रदेव जी की दूसरी "कमेटी" की सिफारिशों के अनुसार तब्दीलियां की जा रही हैं। "हायर सेकेंड्री" शिक्षा के लिये भिन्न-भिन्न पढ़ाइयां कोर्स में रक्खी गई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कायम करने की तैयारियां जारी हैं। इमारतें बन रही हैं और "यूनिवर्सिटी बिल" तैयार हो रहा है। इसके लिये बजट में रुपया भी रक्खा गया है। "लखनऊ यूनिवर्सिटी" को रुपये की मुस्तक़िल सहायता इसलिये दी गई ताकि जे० के० इंस्टीट्यूट आफ सोशियोलोजी एंड हयूमन रिलेशंस के मातहत एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर चलाने के लिये दी गयी। इसी तरह "इलाहाबाद यूनिवर्सिटी" में "रेडियो फिजिक्स" और "इलोक्ट्रोनिक्स" के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्थापित करने के लिये सहायता दी गई। इलाहाबाद और लखनऊ के यूनिवर्सिटियों के कानूनों में संशोधन हो ही रहे हैं।

बजट वर्ष के लिये शिक्षा में सिर्फ ये ही नहीं कि अब तक जो कुछ होता रहा है वही जारी रहे, बल्कि उसकी "क्वालिटी" में उन्नति करने के लिये बन्दोबस्त किया गया है। केंद्रीय सरकार की मदद से "बेसिक" शिक्षा में इस सुधार की एक योजना भी चालू हुई और जूनियर हाई स्कूलों में यह शिक्षा उस प्रकार की होने लगेगी जैसी कि तजवीज की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष के अन्त तक एक आठ साल का मिला जुला "बेसिक" शिक्षा का

"कोर्स" भी जारी होगा। "सेकेंड्री" शिक्षा के "कोर्सों" में उन्नति करने पर ८४ लाख रुपया खर्च किया जावेगा।

"टैक्नीकल" शिक्षा में भी आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं। और इसके जो स्कूल हमारे यहां हैं, उनमें और उनके सामानों में जरूरत के मुताबिक बढ़ोत्तरी की जा रही है। कितने ही स्कूलों की शिक्षा को ऊंचा करके और सामान बढ़ाकर उन्हें इस काबिल किया गया कि वे "हाई स्कूल सर्टिफिकेट" दे सकें। "हारकोर्ट बटलर टैक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट" कानपुर में शिक्षा को ऊंचा किया गया और "आर्ट्स ऐंड क्रैफ्टस स्कूल" लखनऊ में भी उन्नति की गई। शहरों में जो "हायर सेकेंड्री स्कूल" हैं उनमें भी "मिलिट्री शिक्षा" का प्रबन्ध किया जा रहा है।

मेडिकल और पब्लिक हेल्थ

२६—बदकिस्मती से आर्थिक कठिनाई के कारण गवर्नमेंट के लिये अभी तक जरूरत के मुताबिक चिकित्सा की सुविधायें देना मुमकिन नहीं हुआ। फिर भी जहां तक सम्भव हुआ हम उसको बढ़ाते रहे। सन् १९४७ से सन् १९५४ तक पहल इसको दी गई कि जो शफाखाने मौजूद हैं उनकी हालत को ठीक किया जाय और उनसे जो फायदा उठाया जा सकता है उसके दायरे को बढ़ाया जाय और साथ साथ यह कि इनकी संख्या भी इस प्रकार बढ़ाई जाय कि पूरे राज्य के अन्दर उनका एक जाल बिछ जाय। इस उद्देश्य की पाबन्दी में देवरिया, गोंडा, रायबरेली, फिरोजाबाद और खुर्जे में नये शफाखाने बनाये गये। मेरठ, गोरखपुर, देहरादून, बनारस, झांसी, बरेली, कानपुर, फैजाबाद, नैनीताल और इलाहाबाद में जो शफाखाने थे, उनको और बढ़ाया गया और फिर से ठीक किया गया। देहाती क्षेत्रों में "एलोपैथिक" इलाज की कमी को देशी इलाजों का रिवाज करके पूरा किया गया। चुनान्चे आयुर्वेदिक और यूनानी शफाखानों की संख्या २२६ से बढ़कर ५३७ हो गई। छोटे बड़े शफाखानों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनमें सामानों की कमी को पूरा करने की ओर भी ध्यान दिया गया। और यह भी किया गया कि दवाओं के लिये जो रकम दी जाती है वह काफी हो। आम चिकित्सा के अतिरिक्त इस बात की भी कोशिश की गई कि लोगों को इलाज के लिये विशेषज्ञ (specialist) भी मिल सकें। इसके संबंध में जो खास बात की गई वह यह है कि आंख के इलाज (opthalmic relief) को बढ़ाया गया और इस ओर ध्यान दिया गया कि "टी० बी०" के मरीजों के लिये मौजूदा "सैनीटोरियमों" में "बेड्स" की तादाद बढ़ाई जाय। और नये "सैनिटोरियम" खोले जावें। कोढ़ियों के इलाज के लिये शफाखानों और "लैपर ऐसाइलम" को एक लाख उनासी हजार चार सौ रुपये की "ग्रांट" दी गई। चिकित्सा सुविधा में जो इजाफा हुआ उससे यह मसला भी सामने आया कि "ट्रेन्ड पर्सनल" यानी सीखे हुये आदमियों की तादाद बढ़ाई जावे। ताकि वह "सर्विस" में लिये जा सकें। इसलिये "मेडिकल कालेज" आगरा में शिक्षा को ऊंचा किया गया और इसीलिये लखनऊ 'मेडिकल कालेज' में दाखिले की तादाद बढ़ाई गयी थी। इसी के साथ ऊंची तालीम और "स्पेशलिस्ट स्टडी" के साथ दिलचस्पी पैदा करने के लिये "स्कालरशिप्स" देकर ४५ डाक्टर ट्रेनिंग के लिये विलायत भेजे गये और "सर्जरी", "मिडवाइफरी" "गाइनेकोलाजी" (gynaecology) "चेस्ट सर्जरी" और "एनाटोमी" के लिये "पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग" का प्रबन्ध किया गया और "नर्सों" के काम को भी बेहतर करने के लिये इन्तजाम हुआ।

"चालू" वर्ष में शफाखानों की हालत को ठीक करने का काम भी हुआ। और १५ "एलोपैथिक डिसपेंसरीज" १० आयुर्वेदिक और यूनानी "डिसपेंसरीज" कायम की गईं, जिनके स्थापित होने पर "एलोपैथिक डिसपेंसरीज" की संख्या ३६२ और आयुर्वेदिक व यूनानी शफाखानों की तादाद ५४७ हो गई। इस वर्ष में आंखों के इलाज (औप्थेलमिक रिलीफ) को भी बढ़ाया गया और "टी० बी०" के सैनीटोरियमों में 'बेड्स' की और बढ़ोत्तरी की गई। वृन्दावन में ७६ 'बेड्स' का एक "वार्ड" के बनने और इटावे में ३० "बेड्स का" एक "टी०

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बी०" अस्पताल और फाफामऊ में ४५ "बेड्स" का एक वार्ड बनने की भी चालू वर्ष के अन्दर स्वीकृति दी गई। यूनानी और देशी इलाजों को बेहतर बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। "होमियोपैथिक" तरीका-इलाज की तरफ भी तवज्जह की गई। "होमियोपैथिक" डाक्टरों का "ऐक्ट सन् १९५२" के मातहत "रजिस्ट्रेशन" आरम्भ हुआ।

'बजट वर्ष' के अन्दर देहाती रकबे में ३० "एलोपैथिक" २० यूनानी और आयुर्वेदिक "डिसपेंसरियां" खोलने और "मेडिकल" शिक्षा बढ़ाने का प्रबन्ध किया जायेगा और ८,५३,००० रु० इसलिये रक्खे गये हैं कि इनसे इलाहाबाद में बच्चों का शफाखाना खोला जाये। इनके अतिरिक्त 'बजट' के साल में और जो काम करने हैं वह यह हैं--देहाती क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा, शहरी और देहाती क्षेत्रों में बच्चों के पार्क और "हेल्थ-सेंटर्स" "पब्लिक-एनालिस्ट" की "ब्रांच" में इसलिये बढ़ोत्तरी, कि "यू० पी० प्योर फूड ऐन्ड ड्रग्ज ऐक्ट" की और ज्यादा पाबन्दी कराई जा सके और इसके लिये भी रुपया रक्खा गया है कि कानपुर में उन वर्कर्स के लिये जो अपना बीमा करा लें १६४ बेड्स का शफाखाना स्थापित किया जाये, जहां आम बीमारियों और टी० बी० दोनों का इलाज हो। Employees' State Insurance Scheme को अन्य इंडस्ट्रियल towns में लागू करने के लिये भी रुपया रक्खा गया।

कोआपरेशन

२७--सहकारी समितियों के आन्दोलन में उत्तर प्रदेश ने सन् १९४७ में एक नई जान डाली। सहकारी तरीके को विकास और आर्थिक कामों के सम्बन्ध में भी आरम्भ किया गया, न केवल उत्पादन के लिए बल्कि बिक्री और खरीदारी के लिए भी। उसके दायरे में बैंकिंग, "क्रेडिट", इस्तेमाली चीजों और उन चीजों का वितरण जिनकी जरूरत काश्तकारों को होती है--जैसे उन्नति प्राप्त बीज, खाद, खेती के औजार, दूध-घी और दूसरी खेती के पैदावार, "चकबन्दी", सहकारी फार्मिंग, "सिंचाई की समितियां" उत्पादन और मकान बनवाने वाले "कोआपरेटिब्स" हैं। १९५३-५४ के कोआपरेटिव साल में जो खुली सफलता प्राप्त की गयी वह यह है कि "बैंकिंग" और लेन-देन की मशीन को नई बुनियादों पर स्थापित करके उसकी खराबियां दूर की गईं और "प्राइमरी सोसाइटी" से लेकर "यू० पी० के कोआपरेटिव बैंक" तक की इसलाह की गई और उसको, "रिजर्व बैंक" से भी माली इमदाद मिल सकी। समितियां स्थापित कराने के लिए एक "ड्राइव" किया गया जिससे आठ हजार से अधिक नई समितियां स्थापित हुईं। प्राइमरी सोसाइटियों की संख्या पांच लाख तक पहुंच गई। ५० लाख रुपये का "शेयर कैपिटल" इकट्ठा हुआ और एक करोड़ छै लाख रुपया लोगों ने बैंकों में जमा किया और इन बैंकों का "वर्किंग कैपिटल" इस साल में तैंतीस फीसदी बढ़ गया। "कोआपरेटिव" बैंकों ने न सिर्फ वह रुपया काम पर लगाया जो बेकार पड़ा था, बल्कि तीस लाख रुपया गवर्नमेंट से और अस्सी लाख रुपया "रिजर्व बैंक" से लिये। "यू० पी० कोआपरेटिव बैंक" को अपने इतिहास में सब से पहले चार लाख बारह हजार का मुनाफा हुआ।

बाजार की स्थिति के खिलाफ होने के बावजूद "मार्केटिंग" और माल के वितरण में कोई कमी नहीं हुई। "कोआपरेटिव्ज" ने पांच लाख मन खाद साल के अन्दर बांटा। ३३० "कोआपरेटिव" ट्यूबवेल लगे और बहुत सी और नई सिंचाई की समितियां बनाई जा रही हैं। पहाड़ी जिलों में जड़ी-बूटियों की बिक्री पहले से तिगुनी हो गई। दवायें बनाने का एक "प्लान्ट" रानीखेत में लगाया गया। चौहत्तर नये "सीड स्टोर" इस साल में कायम किये गये। इस वक्त सात "मिल्क यूनियन" हैं, जिन्होंने दूध की सप्लाई को बढ़ाया, और कीमत को कम किया। अगले साल की 'बजट' की तजवीजों में मुरादाबाद और देहरादून में एक-एक "मिल्क यूनियन" कायम करना रखा गया है। गुड़ की कीमत घटने की वजह से काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने "कोआपरेटिव फेडरेशन" के द्वारा चार करोड़ रुपये का गुड़ खरीदने का

आदेश दिया। "कोआपरेटिव्ज फेडरेशन" ने खरीदारी शुरू की, जिसकी वजह से कीमत रुकी।

लेबर वेलफेयर

२८--"लेबर" के मामले में भी बहुत सी इस्लाहें की गयीं। राज्य सरकार ने जो 'मशीनरी' "कन्सीलियेशन" के लिए कायम की, उससे झगड़ों और इख्तिलाफों को मिटाने के लिए आपस में सोच-विचार करने के तरीके पर अमल होने से बहुत फायदा हुआ। झगड़ों और कामों के बन्द हो जाने में कमी हो गयी। काम करने वालों की कमाई भी बढ़ गयी। चालू वर्ष में दो "लेबर-वेलफेयर" केन्द्र, झांसी और रामपुर में और खोले गये। उनके खुलने पर कुल संख्या ४० हो जायगी, अलावा उन चार फसली-केन्द्रों के जो शुगर फैक्टरियों में हैं। कानपुर में 'वर्करों' और उनके घर वालों के लिए एक "टी० बी० क्लिनिक" भी खोला गया। "शुगर फैक्टरी हाउसिंग स्कीम" के मातहत सन् १९५४ ई० के आखीर तक ७०० क्वार्टर बन चुके और आशा है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से जो "इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम" चल रही है, उसमें चालू वर्ष के आखिर तक ४,५०० क्वार्टर बन चुकेंगे। अगले साल में "वर्कर्स" के "एडल्ट स्कूल" और बच्चों के घर कानपुर के लिए और तजवीज किये गये हैं। इसकी कोशिश की जायगी कि "शुगर फैक्टरी हाउसिंग स्कीम" के मातहत जो १,५०० क्वार्टर मार्च, सन् १९५६ ई० तक बनने थे, वह बन जावें। यह भी आशा की जाती है कि इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम वाले १३ हजार ९२६ 'क्वार्टर' बजट साल के अन्त तक बन चुकेंगे। यही नहीं, बल्कि और ७ हजार ४ सौ क्वार्टर बनने का काम आरम्भ हो जावेगा।

बाढ़ों की रोकथाम

२९--इस राज्य में वक्तन-फक्तलन बाढ़ों से जान व माल को बहुत नुकसान पहुंचता रहता है। पिछले दिनों ऐसी बाढ़ें आ चुकी हैं जो पहले आती थीं उनसे ज्यादा सख्त थीं। बाढ़ों की रोकथाम के लिये सरकार ने एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (Flood Control Board) कायम किया है, जिसके सुपुर्द यह काम है कि वह थोड़ी देर और ज्यादा देर में होने वाले ऐसे कामों की योजनायें बनाये जिनसे बाढ़ों की रोकथाम हो और इनको चालू कराये। कुछ स्कीमें सरकार ने इस चालू वर्ष के अन्दर भी इस प्रकार की जारी की हैं, जिन पर ३३ लाख रु० खर्च होगा और इसी प्रकार की शार्ट-टर्म (Short term) और लांग-टर्म (Long Term) योजनाएं अगले साल में चालू करने के लिये भी ३८,५८,००० रुपया बजट में रक्खा गया है।

बनारस में गंगा के घाटों को बाढ़ों की जद से बचाना भी बहुत जरूरी है। मौजूदा हालत के लिहाज से कुछ घाट ऐसे हो गये हैं जिनकी दुबारा बनने की जरूरत है और कुछ ऐसे हैं जिनको मरम्मत द्वारा पानी के जद से बचाने की आवश्यकता है। ऐसा न हुआ तो शहर के लिये बहुत खतरा है, इसलिये घाटों के मुताल्लिक एक स्कीम बनाई गई, जिसका खर्चा पन्चानबे लाख नब्बे हजार (९५,९०,०००) रुपया है। मरम्मत की जरूरत के लिहाज से इस योजना के दर्जे यानी फेजेज (Phases) कायम कर दिये गये हैं, और बनारस में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग का एक अस्थायी डिवीजन भी कायम कर दिया गया है, क्योंकि इस काम के लिये चालू वर्ष के बजट में कोई रुपया नहीं था इसलिये (Contingency Fund) से पांच लाख चौबीस हजार दो सौ (५,२४,२००) रुपया लेकर काम आरम्भ कर दिया गया है। बजट वर्ष में ३९,६९,००० रु० इस काम के लिये रक्खे गये हैं।

हरिजन सुधार

३०--राज्य सरकार ने हरिजनों के फायदे के काम करने में खास दिलचस्पी ली है। इस काम पर जहां तक मुझे मालूम है छै लाख रुपया खर्च होता था मगर बजट वर्ष में इसके

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

लिये ७४ लाख रुपया रक्खा गया है। निर्धन हरिजनों के लिए "प्राइमरी" दर्जों से लेकर "यूनिवर्सिटी" तक शिक्षा "फ्री" है। तमाम स्कूलों और कालेजों में उनके लिये जगह "रिजर्व" हैं। उनके वास्ते कानून, इंजीनियरिंग और डाक्टरी जैसे पेशों की तालीम के लिए भी इन्तजाम किया गया है। पेशों और उद्योग-धन्धों का जो केन्द्र लखनऊ में है उसको भी बढ़ाया गया है। और सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित हुआ कि "स्वीपर्स" के लिए मकान बनाये जावें। ३७ म्युनिसिपैल्टियों में २,१५० क्वार्टर बनाने तजवीज किये गये। दूधी, जौंसार बावर और रीवैन में पिछड़े हुये लोगों की हालत बेहतर करने के लिए भी काम किये जा रहे हैं। बजट वर्ष में इसकी भी कोशिश होगी कि हरिजनों को फिर से बसाने का भी इन्तजाम हो। और नैनीताल और गोरखपुर में दो नये उद्योग-धन्धों में "ट्रेनिंग" करने के केन्द्र भी अगले साल पूर्ण रूप से काम करते नजर आयेंगे।

सोशल वेलफेयर

३१—मैंने अपनी स्पीच के पहले हिस्सों में यह अर्ज किया था कि उत्तर प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य है। ऐसे राज्य में "सोशल वेलफेयर" का काम होना भी अत्यावश्यक है। गवर्नमेंट ने उस पर आगे को और ध्यान देने और खुली जिम्मेदारी लेने के लिये इस नाम से एक विभाग खोला है। यह विभाग पूरे राज्य में सामाजिक संस्थाओं और कामों का "सर्वे" कराने वाला है ताकि उनको ऐसी हिदायत और सहायता दी जाय जिससे वह काफी मजबूत हो जायं और अपनी जरूरतें आप पूरी करने वाली बन जायें। यह विभाग इसकी कोशिश करेगा कि इस राज्य में "सोशल वेलफेयर" के लिये एक वातावरण तैयार हो जाये, जिससे लोगों में अपने बुनियादी हकूक के समझने की योग्यता पैदा हो ताकि लोग उन सुविधाओं और मौकों से जो राज्य की ओर से मुहैया किये जायें पूरे तौर पर हिस्सा लें और उनमें खुद "सोशल वेलफेयर" के काम स्थापित करने का उत्साह पैदा हो।

यह डिपार्टमेंट "सोशल वेलफेयर" का एक "डाइरेक्टरेट" भी स्थापित करेगा, जिसका खास काम यह होगा कि "वेलफेयर" के जो काम सरकार की ओर से हों, उनमें और उन कामों में जो गैरसरकारी एजेंसी द्वारा हों, "कोआर्डिनेशन" पैदा करे। इसके अतिरिक्त यह 'डाइरेक्टरेट' कार्यकर्त्ताओं को "सोशल टेक्नीक" की शिक्षा भी देगा, ताकि उनसे सरकार और निजी संस्थायें काम ले सकें। इस "डाइरेक्टरेट" का यह भी काम होगा कि "सोशल" कानूनों को इस निगाह से देखे कि वह आज की समाज की जरूरतों के लिये काफी है या नहीं, और ऐसे ढंग निकाले जिनसे जो कानून "सोशल वेलफेयर" के अहम मसलों के मुतल्लिक मौजूद हैं उन पर पूरी पाबन्दी के साथ अमल हो और समाज में से जिन बुराइयों के खोने की जरूरत है उनके मुतल्लिक नये कानून बनवाये। "सोशल वेलफेयर" के इस "डाइरेक्टरेट" और ऐसी "स्कीमों" पर खर्च करने के लिए जो थोड़े दिनों के अन्दर "ट्रेनिंग" "सर्वे" और "सोशल वेलफेयर" की दूसरी बातों के बाबत बनाई जावें, सरकार ने "टोकन" के तौर पर इस बजट में ५ (पांच) लाख रुपया रखा है और यह हिदायत की है कि और विभागों के "बजटों" में जो रुपया "सोशल वेलफेयर" के कामों के लिए रखा जाता है वह "सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट" को 'ट्रांसफर' किया जावे। इस रुपये के अलावा नीचे लिखी हुई चीजों के लिये "बजट" में और रुपया रखा गया है :—

(१) गूंगे, बहरे और अंधों के स्कूल।
(२) बेवाओं और बच्चों के घर।
(३) यतीमखाने।
(४) महिला-सहायक संघ।
(५) चन्द जिलों में व्यायामशालायें।
(६) औरतों के दो "वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर" पर "होम इकोनामिक्स् सेकशन्स"।
(७) औरतों की "वेलफेयर स्कीम" को छः सात जिलों में बढ़ाना।

ला ऐन्ड आर्डर

३२––अमन के सम्बध में मैं कह सकता हूं कि हालत सन्तोषजनक रही। गांव में जो "डिफेस सोसाइटियां" कायम की गईं उनसे बहुत मदद मिली। यह सोसाइटियां अब तक तमाम गांवों में खोली जा चुकी हैं। गांव के रहने वालों को यह सिखाने के लिये कि डकैतों का कैसे मुकाबला किया जाये, वक्तन-फवक्तन अमली मुजाहिरे कराये गये। इन सोसाइटियों के मेम्बरों ने बहुत से जिलों में विशेषकर बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खीरी, मेरठ, सहारनपुर और देवरिया में डकैतों का बहादुरी के साथ जान की बाजी लगाकर मुकाबला किया और उनकी बदौलत अपराध का मुकाबला करने में आम लोगों से भी बहुत मदद मिली। गांव वालों में जरायम पेशों का मुकाबला जोश के साथ करने के लिए "राइफल क्लब" खोले गये।

पुलिस ने डकैतों का मुकाबला करने में बहुत कामयाबी हासिल की और उनके चंद मशहूर गिरोहों को खत्म किया। उनमें से विशेषकर बयान करने के काबिल यह और इनके गिरोह हैं—चरना, महाबीर, अभिलाख सिंह, गोकुल तेली, बदायूं का शिब्बा, बिजनौर के बल्लन और अटुआ, फतेहपुर का हुसना, सहारनपुर के रूपा व स्वरूप, एटा के जंगलिया और शेर सिंह, मेरठ का विशम्भर सिंह और अलीगढ़ का ईसा। मान सिंह का भी जोर के साथ पीछा किया जा रहा है। पुलिस से लड़ाई में उसके गिरोह के चंद आदमी मारे गये। पुलिस ने जो मुकाबले किये उनमें तहसीलदार सिंह की गिरफ्तारी बहुत कामयाबी की बात थी। बहुत से अहम् मामलों में कामयाबी के साथ पते भी चलाये गये। मसलन् बनारस के गोपाल मन्दिर से सोने और चांदी की चोरी, चलती गाड़ी में से पचास हजार के जेवरों की चोरी, जिस में से करीब-करीब पूरा माल मिल गया और मुलजिम पकड़े गये। गोला की डकैती 'केस' का पता चलने में भी कामयाबी हुई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पुलिस कठिनाइयों का मुकाबला करके गिरफ्तारियां करने व पता चलाने में कामयाब हुई।

लोकल एडमिनिस्ट्रेशन

३३––पंचायतों के स्थापित होने के बाद एक प्रश्न यह पैदा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् और पंचायतों के दरमियान क्या सम्बन्ध हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स रहें या नहीं और अगर रहें तो उनका रूप कैसा हो। डिस्ट्रिक्ट अगर क़ायम रहते हैं तो देहाती क्षेत्रों में टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ही हो या कुछ अख्तियार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास और कुछ पंचायत के पास रहें। इन सब बातों पर विचार करने के लिये गवर्नमेंट ने मिनिस्टरों की एक सब-कमेटी बनाई थी। यह सब कमेटी अपना काम कर चुकी है और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंचने वाली है। इस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट विचार करके निश्चय करेगी कि इन बातों का जो ऊपर बयान की गयीं, फ़ैसला क्या हो। इस समय पंचायतों को पंचायत राज संशोधन अधिनियम के मातहत जो अधिकार प्राप्त हैं वह उनका उपयोग कर रही हैं। इस क़ानून की रु से उनको टैक्स लगाने का भी अधिकार है। जो टैक्स उन्होंने लगाया था उससे इस वर्ष के पहले ६ महीनों में ३९ लाख ८३ हजार रुपये की आय हुई जिसमें से २० लाख १ हजार पब्लिक के फ़ायदे के कामों पर व्यय हुए। मैं अपनी सन् १९५४–५५ ई० की बजट स्पीच में बता चुका हूं कि यह पंचायतें कैसा काम करती हैं। उसके दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शहरों और क़स्बों में बिजली, वाटर वर्कस् और ड्रेनेज के प्रोग्राम बनाये गये। इन प्रोग्रामों में संतोषजनक उन्नति हुई है। सन् १९४६ में इस प्रदेश में २७ क़स्बों में वाटर वर्क्स थे। १९४७ ई० और १९५४ ई० के दरमियान १२ नयी जगहों यानी अल्मोड़ा, गाजियाबाद, बहराइच, मुग़लसराय, राबर्ट्सगंज, हरदोई, पौड़ी और कोटद्वार वगैरा में और स्थापित हुये। सन् १९५३–५४ ई० में एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसके

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

अनुसार २४ नये "वाटर-वर्क्स" और स्थापित होने वाले हैं और मौजूदा में से १५ की खराबियां दूर की जायेंगी। इस योजना में भी काफ़ी काम हो चुका है। चालू वर्ष के अन्दर देवरिया, फिरोजाबाद, गोरखपुर, नजीबाबाद और बस्ती में "वाटर-वर्क्स" का कार्य समाप्त होने वाला है। दूसरे १४ नये "वाटर-वर्क्स" का और १४ "वाटर-वर्क्स" के फिर से ठीक कर देने का काम हो रहा है। काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिये सिर्फ़ यही निश्चय नहीं किया गया कि ३१ मार्च सन् १९५६ ई० तक ही वह काम समाप्त कर दिये जायें, जो मार्च सन् १९५८ ई० तक करने के लिए रखे गये, बल्कि यह भी निश्चय हुआ कि जितनी और "स्कीमें" हाथ में लेकर काम प्रारम्भ किया जा सके, वह भी शुरू किया जावे। बजट-वर्ष के अंत तक ४७ "टाउन" में "वाटर-वर्क्स" का काम समाप्त करने की आशा है।

सन् १९४७ ई० से पहले जमीन के ऊपर चलने वाली नालियों के अलावा सिर्फ़ ५ "टाउन" में जमीन के अंदर नालियां थीं। सन् १९४७ ई० और सन् १९५४ ई० के दरम्यान नैनीताल के नीचे के हिस्से में Sewerage मुहैया किया गया और इसके अलावा आगरे में "ट्रंक सिवेरेज" और दूसरे कबाल (KABAL) "टाउन्स" में "सिवरेज" का रकबा बढ़ाया गया और इसी प्रकार का काम हाथरस, अलीगढ़, बलिया और देवरिया में आरम्भ हुआ।

सन् १९५३–५४ ई० में एक पंच-वर्षीय "प्रोग्राम" १२ "ड्रेनेज" योजनाओं का बनाया गया। इसके काम को भी आगे बढ़ाया गया। कबाल (KABAL) "टाउन्स" में "ड्रेनेज" को बढ़ाने और जो मौजूद हैं, उनको फिर से ठीक करने के अतिरिक्त छै और नई "ड्रेनेज" स्कीमों पर काम होता रहा। मार्च सन् १९५६ ई० तक १६ "टाउन्स" में "ड्रेनेज" का काम समाप्त हो जावेगा।

चालू वर्ष में इस तरफ भी तवज्जह की गई कि छोटे "टाउन्स" और गांवों में भी "वाटर-वर्क्स" की "स्कीम" जारी की जावें। चुनांचे ऐसी एक "स्कीम" बनाई गई। यह "स्कीम" इसलिए बनी है कि इसके अनुसार बिजली की लाइन के पास स्थित एक हजार गांवों में मार्च सन् १९५६ ई० तक नलों द्वारा "वाटर-सप्लाई" का प्रबन्ध हो जाये, इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से रुपया हासिल करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। जितना रुपया वहां से मिलेगा उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार technical सुपरविजन पर व्यय करेगी। जहां तक होगा श्रमदान से भी इसमें सहायता ली जावेगी।

टैक्स

३४—मैंने चालू वर्ष की बजट स्पीच में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार यह चाहती है कि पहिली पंचवर्षीय योजना का काम कोई नया टैक्स लगाये बगैर समाप्त किया जाय सन् १९५५–५६ के इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस बजट में जो अंदाजे आमदनी व खर्च के रक्खे गये हैं वह यह बताते हैं कि सरकार को नई आमदनी पैदा करने की बहुत आवश्यकता थी मगर यह इरादा कर लिया गया था कि टैक्स लगाये बगैर प्लैन के काम को पूरा किया जाय, इसलिये टैक्स लगाने से बचा गया। टैक्स लगाने के बजाय यह किया गया कि सेल्स टैक्स में और जरायती टैक्स में जिस हद तक मुमकिन हुआ, चालू वर्ष में exemptions और सहूलियतें दी गईं। सेल्स टैक्स से उत्तर प्रदेश को लगभग ५ करोड़ की सालाना आमदनी है और उसके मुकाबिले में मद्रास और बम्बई को १४ १/२ और १३ करोड़ की। यहां कम आमदनी होने के बावजूद चालू वर्ष के अन्दर १२ ऐसी चीजों का कर माफ किया गया जिनका संबंध घरेलू उद्योग-धंधों से है। वह चीजें यह हैं—दरी, निवाड़, हैन्डलूम्स के बने हुये ऊनी कालीन, चिकन, ताले, क्वालिटी निशान लगी हुई हाथ की बनाई हुई कैंचियां व चाकू, हाथी दांत और संगमरमर की बनी हुई चीजें, लकड़ी की नक्शीन चीजें, कार्डबोर्ड के वर्क्स और पैमाइश में काम आने वाले औजार। इनके अलावा सत्रह

चीजें ऐसी हैं जिनपर बरायनाम फीस ली जाती है और कोई टैक्स नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट ने हाल में एक कमेटी बैठाई है, जो सेल्स टैक्स के तशखीस करने के तरीकों को जांचेगी। वह कमेटी यह भी देखेगी कि जिन चीजों को टैक्स से बरी कर दिया गया उनकी फेहरिस्त में किसी तरमीम की जरूरत है या नहीं। साथ ही साथ सेल्स टैक्स को गलत तरीके से बचाने के मसले पर भी इस कमेटी को गौर करना है। इस कमेटी के अलावा यू० पी० Handloom Board की एक सब-कमेटी घरेलू उद्योग-धंधों से पैदा किये गये सामान पर sales tax का जो असर है उस पर विचार कर रही है।

सेल्स टैक्स में रियायतें देने के अतिरिक्त कृषि कर के सिलसिले में भी "कृषि संशोधित अधिनियम सन् १९५४ ई०" के अनुसार कुछ रियायतें दी गई हैं—मसलन इन संशोधनों के होने के पहिले तीन हजार रुपया और उससे ऊपर की आमदनी पर टैक्स लिया जाता था अब चार हजार दो सौ और उससे ज्यादा की आमदनी पर टैक्स लिया जाता है। टैक्स देने वालों को तशखीस कराने की दिक्कतों से बचाने के लिये यह भी कर दिया गया है कि सरकार की ओर से उनको तशखीस की इत्तिला भेज दी जाये और वह घर बैठे जो कुछ एतराज करना चाहें, कर दें। बागों की आमदनी के सिलसिले में भी आसानी कर दी गई है कि टैक्स बाग की जमीन के लगान के हिसाब से लिया जाये। तरमीम से पहिले कानून यह था कि टैक्स देने वाले को अधिकार था कि आमदनी की तशखीस पर टैक्स लगवाये या लगान के multiple पर। यह एक दफा तय करके बता देना होता था जिसके बाद इसमें कोई तब्दीली बगैर बोर्ड आफ रेवेन्यू की इजाजत के नहीं हो सकती थी, परन्तु संशोधन ने यह हक दे दिया कि टैक्स देने वाला जिस साल भी चाहे बदल ले, किसी की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं।

मकानों की कमी

३५—उत्तर प्रदेश में चंद साल से मकानों की कमी महसूस हो रही है। राज्य सरकार ने इस मसले पर एक "कमेटी" बैठाई, जो मकानात के बनाने के सिलसिले में यह बताये कि कितनी कमी है और इसको पूरा करने के लिये क्या-क्या करना जरूरी है, यह "कमेटी" चालू वर्ष में बिठाई गई थी। जो अभी अपना काम कर रही है और थोड़े दिनों में खत्म करने वाली है। इस "कमेटी" ने एक "सर्वे" कराया, जिससे मालूम हुआ कि अगर "इन्डस्ट्रियल हाउसिंग" के सिलसिले में जो मकान अब तक बन चुके हैं, उनको गिनती में न लिया जाय, तो एक लाख चौंतीस हजार मकानात की कमी है और "सर्वे" करने वालों ने राय दी है कि अगर बत्तीस हजार मकानात बना दिये जायें, तो माकूल हद तक यह कमी दूर हो जावेगी।

आशा है कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय सरकार से तीन करोड़ रुपये का ऋण मकानात बनाने के लिये बजट वर्ष में मिलेगा। यह रुपया उन लोगों को मिल सकता है जिनकी आमदनी ६,००० रुपया सालाना या उससे कम हो। यह भी शर्त है कि मकान की लागत आम तौर से दस हजार रुपये से ज्यादा न हो।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स

३६—कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की लाइन्स पर काम करने का भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इरादा किया जिसकी बिना पर एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट इटावे में शुरू किया गया उसमें जो काम हुआ उसकी सफलता ने दिमाग़ों को अपनी तरफ खींचा। आज उत्तर प्रदेश में २६ (छब्बीस) कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें ६ हजार (६,०००) मुरब्बा मील रक़बे पर जिसमें छब्बीस लाख (२६,००,०००) आबादी है, काम हो रहा है, जहां खेती की उन्नति के लिये अच्छा बीज, खेती के औजार और खाद दिया जाता है। सिंचाई का भी प्रबन्ध किया जाता है और मौजूदा जमाने के नये ढंगों से खेती के कामों को करना भी सिखाया जाता है। इन इलाकों में सीड सैचुरेशन (Seed saturation) का काम इतना बढ़ा हुआ है कि गेहूं के मुताल्लिक

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

पचहत्तर फीसदी और चने और जौ के मुताल्लिक पचास फीसदी उन्नति उन ब्लाक्स में हो चुकी है जो सन् १९५२ ई० में खोले गये थे। जहां इन ब्लाक्स में अनाज की पैदावार बढ़ाने की कोशिश हो रही है वहां फलदार बाग लगाने और तरकारियां उगाने का काम भी किया जा रहा है। बागों के अलावा जंगलात लगाने का काम भी हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को इन कामों से, जो इन इलाकों में हो रहे हैं, बहुत दिलचस्पी पैदा हो गयी है। सिंचाई के बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। चुनांचे एक लाख अस्सी हजार (१,८०,०००) एकड़ जमीन के लिये सिंचाई का प्रबन्ध हो चुका है और उम्मीद की जाती है कि मियाद के अन्दर कुल रक़बे के पचास फीसदी के लिये सिंचाई का इन्तजाम हो चुकेगा। श्रमदान द्वारा सड़कें बनाने और काटेज इन्डस्ट्रीज (Cottage Industries) का काम भी खूब बढ़ा है और लोगों ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली है। घरेलू उद्योग-धन्धों की उन्नति पर जोर देने के लिये इन्डस्ट्रीज विभाग ने एक ज्वाइन्ट-डाइरेक्टर भी मुकर्रर किया है जो खास तौर से इस काम की ओर ध्यान देगा।

३१ मार्च सन् १९५४ ई० को इस राज्य में इकतालीस (४१) एन० ई० एस० ब्लाक्स पर काम हो रहा था। दो अक्तूबर सन् १९५४ ई० को १५ और २६ जनवरी सन् १९५५ ई० को ३८ ब्लाक और खोले गये। इस तरह सब मिलाकर ९४ ब्लाक्स हो गये जिनमें तेरह हजार (१३,०००) गांव हैं और पचास लाख (५०,००,०००) आबादी है।

चूंकि कम्युनिटी-प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स में काम करने के लिये ट्रेनिंग देना आवश्यक था इसलिये बख्शी के तालाब पर मई सन् १९५२ ई० में एक ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया और उसके बाद २४ सेन्टर ऐसे खोले गये जिनमें ट्रेनिंग भी होती है और एक्सटेन्शन का काम भी होता है। जो लोग इस वक्त तक ट्रेनिंग पा चुके हैं उनकी संख्या दो हजार आठ सौ बत्तीस (२,८३२) है। मई सन् १९५४ ई० में अपनी प्रकार का भारत में एक सबसे पहला प्लानिंग रिसर्च और ऐक्शन इन्स्टीटयूट (Planning Research and Action Institute) खोला गया जिसमें खास चीफ़ मिनिस्टर साहेब की निगरानी में काम होता है। यह इन्स्टीटयूट इस लिये खोला गया कि इसके द्वारा काम करने वाले सरकारी मुलाजिमों और गैर सरकारी लोगों में से प्लानिंग डेवलपमेन्ट प्रोग्राम तथा और तरीकों के क़ायम करने के माहिर (Specialist) पैदा किये जायं। इस इन्स्टीटयूट के लिये जिले इटावा और जिला लखनऊ को फील्ड-लेबरेटरी क़रार दिया गया है।

अगले साल इन ब्लाक्स में उन कामों पर जो हो रहे हैं और ज्यादा जोर दिया जायेगा ताकि काम का जो टारगेट मुक़र्रर किया गया है वह वक्त के अन्दर पूरा हो जाय, बल्कि बाज चीजों में टारगेट से भी ज्यादा काम हो जाय। एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिये यह तजवीज है कि इन ४१ ब्लाक्स में से जो सन् १९५३-५४ ई० में शुरू किये गये बीस इन्टेन्सिव-डेवलपमेन्ट ब्लाक्स हो जायं, जिनमें कम्युनिटी डेवलपमेन्ट-ब्लाक्स के तरीकों पर काम हो। इसके अतिरिक्त यह भी इरादा है कि अगले साल ३० नये ब्लाक्स और खोले जायं और उनके साथ ट्रेनिंग पर भी और जोर दिया जाय।

श्रमदान

३७--श्रमदान ने हमारी स्टेट में एक खास जगह, शोहरत और हर दिल अजीजी हासिल कर ली है। इसकी तरफ लोगों ने उत्साह के साथ ध्यान दिया है। जो तजुर्बा दिसम्बर सन् १९५२ ई० में आरम्भ किया गया था वह कामयाब साबित हुआ। दिसम्बर सन् १९५२ ई० के बाद और ड्राइव (Drives) भी किये गये। उनमें भी उसी उत्साह और दिलचस्पी का इजहार हुआ और इस वजह से जो नतीजे सामने आये वह आशा से भी अधिक थे। श्रमदान तेजी के साथ एक क़ौमी-तहरीक बनता जा रहा है। यहां यह बात भी कहने

के काबिल है कि जो विकास मुकामी तौर पर सब जगह हो रहा है बहुत हद तक वह इसी आन्दोलन के कारण है। जो काम किया गया है उसमें बहुत कामयाबी हुई। पन्द्रह हजार एक सौ उन्तालीस (१५,१३९) मील सड़कें बनीं, एक हजार सोलह (१,०१६) बन्धियां, चार सौ पच्चासी (४८५) कुंयें, आठ सौ उन्नीस (८१९) पंचायतघर और एक सौ निन्नानबे (१९९) स्कूलों की इमारतें श्रमदान द्वारा तैयार हुईं। इस सफलता से साबित होता है कि इस प्रदेश में गांव-गांव लोग जाग गये। यह बात आइन्दा की कामयाबी में बड़ी सहायता देने वाली है।

बेरोजगारी का इलाज

(Relief of Unemployment)

३८—बेरोजगारी बहुत बुरी चीज है और समाज की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये इसका खोना बड़ा आवश्यक है। आजकल देश में इसकी ओर सभी का ध्यान आकर्षित है। जहां तक मैं जानता हूं, इसके मुताल्लिक अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ कि यह कितनी है। यू० पी० में इसकी ओर इकोनौमिक एण्ड स्टेटिस्टिकस डिपार्टमेंट (Economics and Statistics Deparment) ने कोशिश की है कि इसकी संख्यायें प्राप्त हों। इस विभाग के जो इन्सपेक्टर्स गांव में रहते हैं, उनके जरिये से जो मालूमात हासिल की गई हैं, उसके बिना पर देहाती रकबे के आंकड़े (Statistics) तैयार हुये हैं, और फैक्टरी वर्कर्स की बाबत भी थोड़ी सी जानकारी हासिल की जा सकी है, इससे ज्यादा और अभी जानकारी नहीं मिली। और शहरी रक़बे के निस्बत नहीं कहा जा सकता कि वहां बेरोजगारी का प्रतिशत औसत क्या है।

देहाती रकबे की बाबत यह मालूम हुआ है कि वहां तीन-चार फीसदी लोग बेकार हैं, और बाक़ियों में से पैंतीस (३५) फीसदी लोग वह हैं, जो पूरे तौर पर रोजगार वाले हैं, यानी उनको आठ घंटे रोजाना काम मिलता है, बाकी साठ-बासठ फीसदी वे लोग हैं, जिनको सिर्फ साढ़े छः घंटे रोजाना का काम मिलता है। अगर हम यह मानें कि जिसको पूरे आठ घंटे रोजाना का काम न मिलता हो उसको कम रोजगार वाला, समझा जाय, तो पूरे रोजगार वाले सिर्फ पैंतीस (३५) फीसदी हैं। अगर बरखिलाफ़ इसके यह माना जाय कि साढ़े छः घंटे काम को भी पूरा रोजगार समझा जाय तो तीन-चार फीसदी के अलावा बाकी के बाबत यह मानना होगा कि सब को पूरा रोजगार मिला हुआ है।

फैक्टरी के वर्कर्स की सूरत यह है कि उनकी संख्या जो १९५१ में २,०२,५०० थी से बढ़ कर १९५३ में २,०६,७०० हो गई है, यानी उनकी संख्या में ४,२०० की बढ़ोत्तरी हो गई है। गोया फिलहाल इनके मुताल्लिक बेरोजगारी की शिकायत नहीं मालूम होती।

सरकार ने बेरोजगारी खोने के लिये, कई योजनायें प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये भेज रक्खी हैं। कृषि इस प्रदेश में जिस सीमा तक पहुंच गई है, उसके बाद इस पेशे में और आदमियों के दाखिल होने की गुंजाइश नहीं है, इसलिये आवश्यक है कि छोटे और घरेलू उद्योग धन्धों को बढ़ाकर उनसे लोगों के लिये रोजगार पैदा किया जाय। इसलिये, जैसा कि खुद प्लानिंग कमीशन की भी राय है, इसकी आवश्यकता है कि उद्योग धन्धों की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया जाये। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जह कर रही है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी उसने ऐसे धन्धों को मुख्य जगह दी है। मैंने इस स्पीच में उद्योग धन्धों की बाबत कहते हुये इस प्रकार की कुछ बातों का चर्चा किया है और इसी स्पीच में यह भी बतलाया है कि सरकार ने पढ़े-लिखों के लिये टेक्निकल ट्रेनिंग और पेशों के काम सीखने के लिये सुविधायें पैदा कर दी हैं, और पैदा करने जा रही है।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मैं अन्त में यह बता देना आवश्यक समझता हूं कि सरकार बेरोजगारी को एक महत्वपूर्ण चीज ख्याल करती है जिसकी ओर ध्यान देना और बिला लिहाज इस बात के कि इन संख्याओं से क्या नतीजे निकलते हैं, उसको जल्द से जल्द खोना बहुत आवश्यक समझती है। इसीलिये अगली पंचवर्षीय योजना में उसको सबसे पहली जगह दी जाने वाली है। इन दिनों भी सरकार ने उसको मिटाने की योजनाएं चला रक्खी हैं।

आर्थिक संवृद्धि या माली खुशहाली

३९—विकास का जो हाल बयान किया गया है उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि आखिर उसका परिणाम क्या है, जिसका मतलब यह है कि विकास से यहां के रहने वालों की माली हालत में किस सीमा तक बेहतरी हुई। मेम्बरान जानते हैं कि विकास का कार्य सन् १९४६ ई० में प्रारम्भ हुआ और सन् १९४७ ई० से उसको बढ़ाना शुरू किया गया। विकास के कामों में से जिन पर विशेष ध्यान दिया गया वह कृषि, सिंचाई के साधन, पशुओं की उन्नति, जंगलात, बिजली, उद्योग-धन्धे, यातायात, पब्लिक हेल्थ और शिक्षा वगैरा है। यह चीजें आदमी की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाली हैं।

न सोचा गया और न यह मुमकिन ही था कि वह तमाम योजनायें जिनसे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, एक साथ जारी कर दी जायें। उनको धीरे-धीरे और दर्जे-बदर्जे हाथ में लिया जा सकता था। उनमें से कुछ १९४७ ई० में प्रारम्भ की गईं और बाकी उसके बाद के आने वाले वर्षों में। उसका नतीजा यह है कि उनमें से कुछ समाप्त हो चुकी हैं और कुछ समाप्त होने के निकट हैं और कुछ अपनी प्रगति के मध्य में हैं। जाहिर है कि इनका सामूहिक फल इतने थोड़े अर्से में जितना कि अब तक बीता है पूर्णरूप से सामने नहीं आ सकता था बल्कि जो योजनायें पूरी हो चुकी हैं उनका भी लाभ अभी पूरे तौर पर विदित नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसके लाभदायक फल तकरीबन हर दिशा में दिखाई देने लगे हैं। सड़कों का एक जाल उत्तर प्रदेश की लम्बाई व चौड़ाई में हजारों मील फैल चुका है। बहुत से नेशनलाइज्ड रूट्स पर सरकारी बसों के बेड़े दौड़ते नजर आते हैं। सैकड़ों ट्यूबवैल, हजारों मील नहरों की शाखें, अनेक सिंचाई के बांध, पावर स्टेशन और सैकड़ों सब-स्टेशन बन चुके हैं। सैकड़ों मील ट्रान्समिशन लाइन तैयार हो चुकी है। लाखों एकड़ नई भूमि काश्त में आ चुकी है, सैकड़ों बीजगोदाम, स्कूल, टेक्निकल संस्थायें, अस्पताल, फैक्ट्रियां और वर्कशाप स्थापित हो चुके हैं और सबसे ज्यादा यह कि खाद्य का मसला (प्रश्न) सफलता से हल हो चुका है। यह सब उस अथक कोशिश की गवाही देते हैं जो उत्तर प्रदेश में आर्थिक संवृद्धि लाने के लिये की गई हैं।

यह बात अनुमान में भी नहीं आ सकती कि ऐसी मूल्यवान चीजें जिन पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा चुका है, मालूम होने वाला लाभ पहुंचाने में असफल रहें और इस प्रदेश में आम खुशहाली न बढ़ायें। निश्चय रूप से उनसे खुशहाली बढ़ी है, जो अन्त में सूरज की तरह चमकेगी और सबके हृदयों में गर्मी और खुशी पैदा करेगी।

अगरचे आंकड़ों से जो नतीजे निकलते हैं वह चुप करने वाले नहीं होते परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक संवृद्धि की झलक आंकड़ों ही में देखना चाहते हैं उनके लिये मैं ऐसे आंकड़े पेश करता हूं, जो यह बतलायेंगे कि इस प्रदेश में खुशहाली का प्रभात आ चुका है। कृषि की उन्नति खेती के रकबे की बढ़ोत्तरी के रूप में एक सही और मजबूत बुनियाद पर स्थापित हो चुकी है। सन् १९५३–५४ ई० में यह रकबा तीन करोड़ चौरानबे लाख एकड़ से अधिक पहुंच चुका था जो सन् १९५१–५२ ई० के रकबे से साढ़े तीन लाख एकड़ अधिक है। हमने जो ध्यान खाद्य की पैदावार बढ़ाने पर दिया उसका फल यह है कि अगर उस पैदावार को सन् १९४८–४९ ई० में सौ माना जाये तो वह सन् १९५२–५३ ई० में एक सौ ग्यारह और सन् १९५३–५४ ई० में एक सौ तेरह हो गई। यह विशेष तौर पर नोट करने के काबिल है कि यह बढ़ोत्तरी अधिकतर चावल व गेहूं की पैदावार में हुई। खाद्य के बाद दूसरे नम्बर की आवश्यकता कपड़ा है, उसकी

तैयारी बढ़ाने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि उत्तर प्रदेश में अच्छे किस्म की रुई की पैदावार ज्यादा की जाय। यह पैदावार बढ़ी और इतनी बढ़ी कि सन् १९४८ ई० में अगर ३,०९३ लाख गज कपड़ा बना था तो सन् १९५३ ई० में ३,४९२ लाख गज कपड़ा बना, यानी ३९९ लाख गज ज्यादा। उत्तर प्रदेश में स्टील भी बनता है, यह ऐसी इन्डस्ट्री है जिसका सम्बन्ध अधिकतर केन्द्रीय सरकार से है, परन्तु उसकी पैदावार का सीधा असर इस प्रदेश के राष्ट्र धन पर होता है लिहाजा जो बहस इस समय है उसके सम्बन्ध में यह दिखा देना उचित है कि उस इन्डस्ट्री में क्या उन्नति हुई। स्टील की पैदावार सन् १९५० ई० में २१,६०० टन थी जो सन् १९५३ ई० में २३,५०० टन हो गई और सन् १९५५ ई० में उससे बढ़कर २८,६०० टन हो गई। अन्य छोटे व बड़े उद्योग-धन्धों में जो उन्नति उत्तर प्रदेश ने की है उसका चर्चा पहिले किया जा चुका है जिसके दोहराने की यहां आवश्यकता नहीं। मैं यहां केवल शक्कर की और चर्चा करूंगा। यू० पी० में फैक्टरियों के जरिये से शक्कर भी बनती है। इस वक्त यहां ६७ फैक्टरियां हैं। इन फैक्टरियों से बनने वाली शक्कर की पैदावार सन् १९४६–४७ ई० में ५.५१ लाख टन थी जो बढ़ते-बढ़ते सन् १९५२–५३ में ७ लाख टन हो गई। शक्कर की पैदावार एक ऐसी चीज है जिसमें वक्तन-फवक्तन कमी-ज्यादती होना कुछ ताज्जुब की बात नहीं, इसलिये कि ईख के रकबे में और फैक्टरी में पहुंचने वाले गन्ने की मात्रा में भिन्न-भिन्न कारणों से कमी-बेशी होती रहती है।

जहां इन्डस्ट्री में उन्नति हुई है वहां मिल वर्कर्स की मजदूरी भी बढ़ी है। यह आमदनी १९५० ई० में आठ सौ अस्सी रुपया सालाना फी वर्कर थी जो बढ़ कर सन् १९५३ ई० में नौ सौ पैंतालीस रुपये हो गई। अगर सन् १९३९ ई० में मिल वर्कर की मजदूरी को सौ माना जाय तो सन् ४७ में घटकर ९२ रह गई मगर फिर सन् ५३ में बढ़ कर १२७ हो गई।

उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में कहते हुये मैं पहले यह बता चुका हूं कि इन धन्धों से बनने वाली बहुत सी चीजें उत्तर प्रदेश से बाहर जाती हैं। इसी तरह कृषि सम्बन्धी पैदावार भी इस राज्य से बाहर दूसरे प्रदेशों और देशों को जाती रहती है। जो आयात (Import), निर्यात (Export) उत्तर प्रदेश में होती है इस पर उससे प्रकाश पड़ता है कि निर्यात आयात से अधिक है।

उत्तर प्रदेश की खालिस निर्यात अगर सन् १९४८–४९ में १०० थी तो १९५२–५३ में १३३ हो गई यानी ३३ फीसदी बढ़ गई।

लोग माली खुशहाली का अनुमान राष्ट्रधन से भी करते हैं। सन् १९४८–४९ ई० की कीमतों पर राष्ट्रीय आय कायम करने से हमारे सामने यह नतीजा आता है कि अगर यह धन इस साल पन्द्रह अरब सताइस करोड़ था तो १९५३–५४ ई० में सोलह अरब अड़सठ करोड़ हो गया यानी सन् १९४८–४९ ई० के मुकाबले में १९५३–५४ में नेशनल इनकम में एक अरब एकतालीस करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। मगर याद रहे कि यह आंकड़े १९४८ की कीमतों की बिना पर निकाले गये हैं। अगर फी कस आमदनी देखना है तो सन् १९४७–४८ ई० में २१७.८ रुपये थी और १९५२–५३ ई० में २४१.८ रुपये हो गई। फीकस औसत में यह बढ़ोत्तरी बावजूद इस बात के हुई कि १९५१ में उत्तर प्रदेश की आबादी ६६.८ लाख बढ़ गई।

इससे पहले कि मैं माली खुशहाली पर कहना खत्म करूं, मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि आर्थिक दायरे में बहुत उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इस उतार-चढ़ाव का असर आंकड़ों पर पड़ता रहता है, इसलिये ज्यादा सही बात यह है कि राय उत्पादन की मात्रा पर कायम करना चाहिये। कृषि ऐसी चीज है जिसमें फसलवार उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी है जिसको ज्यादातर कृषि इकानामी कह सकते हैं। ऐसी इकानामी में उत्पादन की कसौटी भी उतार-चढ़ाव की वजह से बिल्कुल सही नतीजों तक नहीं पहुंचाती।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इसलिये गवर्नमेंट की कोशिशों के नतीजों के साथ समझने के लिये यह देखना चाहिये कि गवर्नमेंट ने उत्पादन के साधन कितने पैदा किये और किस हद तक बढ़ाये। अगर इस कसौटी पर जांचा जाय तो कोई सन्देह नहीं कि गवर्नमेंट की कोशिश सराहनीय समझी जायेगी।

बजट की कुछ विशेष बातें

४०—बजट वर्ष में जो नये खर्चे रखे गये हैं, उनमें से चन्द मेरे नजदीक इस काबिल हैं जिनके निस्बत इस वक्त कुछ कहना चाहिए। यह बात कि क्यों इनका खासतौर पर जिक्र किया जाये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इस 'स्पीच' के सुनने वाले और पढ़ने वाले खुद यह समझ लेंगे कि क्यों इनकी चर्चा की गयी। वह बातें ये हैं :—

"इनफार्मेशन डिपार्टमेंट" खुद फिल्म तैयार करने वाला है। लखनऊ में एक स्थायी प्रदर्शिनी कायम की गई और हर जिले में एक "इन्फार्मेशन सेंटर" खोलने के लिए रुपया रखा गया है।

बनारस में "संस्कृत युनिवर्सिटी" खोलने के लिए १ लाख रुपया रखा गया है और तीस हजार रुपया संस्कृत की किताबें लिखवाने के लिए। इनके अलावा हिन्दी-उर्दू में किताबें लिखने वालों के लिए भी रुपया रक्खा गया है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि जरा हट कर इस जगह पर यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यह मानती है कि इस प्रदेश में उर्दू भी बोली जाती है और बहुत से बच्चों की मादरी जबान है। चूंकि सरकार इस उसूल को मानती है कि एक खास उम्र तक बच्चों को शिक्षा उनकी मादरी जबान में मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने यह बन्दोबस्त कर दिया कि जिन स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले मुक़र्रर संख्या में मौजूद हों, वहां उर्दू टीचर दिया जाये। उसकी देख-भाल के लिए एक खास अफसर मुकर्रर है जिसका यह काम है कि जहां जरूरत हो, वहां इसका इन्तजाम कराये। यह मालूम होने पर कि उर्दू में कोर्स की किताबें छपी हुई नहीं मिलतीं, राज्य सरकार ने उनको खुद छपवाया। श्री गोविन्द-वल्लभ पन्त साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर और डा० सम्पूर्णानन्द मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर इस सदन में यह बयान दे चुके हैं कि सरकारी दफ्तरों में दरख्वास्तें उर्दू में भी दी जा सकती हैं। चूंकि इस प्रदेश में उर्दू भी बोली जाती है, इसलिए सरकार को उर्दू की हर वह मदद करने में तअम्मुल नहीं, जो सरकार की तरफ़ से किसी ग़ैर सरकारी ज़ुबान की की जानी चाहिए।

जुलाई, १९५५ में पांच सौ 'प्राइमरी स्कूल' खोलने के लिए रुपया रखा गया। गांवों में "लाइब्रेरियां" खोलने के लिए ७५ हजार रुपये रक्खे गये हैं और शहरी रकबे में देने के लिए ४० हजार, जो कि इलाहाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ की अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी और काशी विद्यापीठ लाइब्रेरी के दरमियान तकसीम किया जायेगा।

यहां मैं इस बात का भी तजकिरा करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटीज़ ग्रान्ट्स कमेटी की तजवीज के मुताबिक़ यह फ़ैसला किया गया है कि इलाहाबाद और लखनऊ युनिवर्सिटी में रीडर और प्रोफेसरान की तादाद निस्बतन ज्यादा रक्खी जाय और इसके लिए बजट में रुपया रक्खा गया है। मेम्बरान को मालूम है कि पिछले चन्द सालों में इन युनिवर्सिटियों के जिम्मे बहुत क़र्ज़ा हो गया है। इस खास मामले में गवर्नमेंट ने यह कुबूल कर लिया था कि यह कर्जा सरकार अदा कर दे। चूंकि अभी तक अदा नहीं हुआ और युनिवर्सिटियों के जिम्मे सूद चढ़ रहा है, इस वजह से दोनों को एक एक लाख रुपये की ग्रांट रक्खी गयी है, ताकि सूद अदा हो।

लखनऊ का अजायबघर दो अलग-अलग इमारतों में बंटा हुआ है जिससे उसका काम ठीक नहीं चलता। उसके साथ ही साथ यह भी बात है कि अजायबघर का एक हिस्सा लखनऊ के म्यूजिक कालेज की इमारत का एक भाग घेरे हुए है और इससे म्यूजिक कालेज के काम में बाधा पड़ती है, इसलिये म्यूजियम के लिये एक अलग इमारत बनाने की तजवीज

की गयी है। इसकी पूरी लागत ८ लाख रुपया होगी और बजट वर्ष में काम प्रारम्भ करने के लिये २ लाख रुपया रक्खा गया है।

मैंने इस स्पीच में पहले भी जिक्र किया है कि देहातों में सफाई और नल से पानी पहुंचाने की योजनाओं के लिये ९४.५ लाख रुपया बजट में रक्खा है। ३ करोड़ रुपया कम आमदनी वालों के लिए मकान बनाने की स्कीम के लिए रक्खा गया है, जिसका तजकिरा मैं पहले भी कर चुका हूं।

लगभग एक लाख सत्तर हजार रुपया मेडिकल डिपार्टमेंट में इसलिये रक्खा गया है कि उससे एक हेल्थ म्यूजियम खोला जाये और बच्चों की तन्दुरुस्ती के केन्द्र कायम किये जायें।

दो लाख रुपया जिन निर्धन स्त्रियों के बच्चे पैदा होने वाले हों, उनमें दूध तकसीम करने के लिये रक्खा गया है। शुरुआत के तौर पर इस योजना को काशल टाउन्स में और दो देहाती क्षेत्रों में जिनको गवर्नमेंट तजवीज करेगी आजमाया जायेगा। सरकार यह चाहती है कि बूढ़े, बीमार, कमजोर लोग जिनके लिये कहीं शरण की जगह नहीं है उनके लिए एक खास बन्दोबस्त इस राज्य में होना चाहिये, अगले वर्ष में इसको आरम्भ करने के लिए तीस हजार रुपया रखा गया है। जहां तक ख्याल है, यह रुपया लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को दिया जायगा, क्योंकि यह म्युनिसिपैलिटी इस प्रकार का कुछ काम पहले से ही सेवा सदन द्वारा कर रही है। सरकार यह चाहती है कि इस काम को और बढ़ाया जाये और सारे राज्य की जरूरियात मालूम करने के लिए एक सर्वे (Survey) करवाया जाये। यह रुपया जो इस बजट में रक्खा गया है, केवल इसलिए है कि इस वक्त यह काम यहां शुरू कर दिया जाये।

रेगिस्तान को उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकने के लिए नौ लाख साठ हजार रुपये रक्खे गये हैं ताकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरहद पर जो जंगल उगाने का काम हो रहा है, उसको और बढ़ाया जाय। दो लाख पचहत्तर हजार रुपये इसलिए रक्खे गये हैं कि चारे (Fodder) की घासों के सम्बन्ध में रिसर्च की जाये।

एक लाख तिरपन हजार पांच सौ रुपये इसलिये रक्खे गये हैं कि रुई की स्कीम को और बढाया जाय।

एक लाख चालीस हजार रुपये भूमि संरक्षण (Soil Conservation) के लिये और चालीस हजार रुपये पहाड़ी इलाकों में रिसर्च सब-स्टेशन कायम करने के लिये रक्खे गये हैं।

एक लाख रुपया इसलिये रक्खा गया है कि एक जिओलाजिस्ट (Geologist) और उसका स्टाफ (Staff) मुकर्रर किया जाये जो प्रदेश में जगह-जगह सर्वे किया करे। इसकी जरूरत इसलिये हुई कि कई किस्म की इंडस्ट्रीज में खनिज पदार्थ (minerals) की जरूरत पड़ती है। छोटे उद्योग और घरेलू धंधों के सर्वे (survey) के लिये भी एक लाख रुपया रक्खा गया है ताकि ऐसे धंधों को बढ़ाने में इमदाद दी जा सके।

पुलिस के संबंध में २३ लाख ३६ हजार ९ सौ रुपया इसलिये रक्खा गया है कि पुलिस के हेड-कांसटेबुलों और कांसटेबुलों को चार (४) रुपया फी कस खूराक एलाउन्स दिया जाये।

बहुत से जुडिशल अफसर (Judicial Officer) कई सालों से अस्थायी (temporary) चले आ रहे हैं। यह फैसला किया गया है कि उनमें से ६० मुस्तकिल कर दिये जायें। यह भी तय किया गया है कि उनकी तनख्वाह पी० सी० एस० अफसरान के बराबर कर दी जाये।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

अगले वर्ष एक मुस्तक़िल लेडी प्रोबेशन अफसर मुकर्रर करने की भी तजवीज की गई है कि वह उन औरतों की जेल से छूटने के बाद देख-भाल करे, जो नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ और दूसरी जगहों में रक्खी जाती हैं। इस बात के लिये भी रुपया रक्खा गया है कि सब प्रोबेशन अफसरों (Probation Officers) की पे स्केल (Pay Scale) बराबर कर दी जाये।

एक लाख रुपया पहले से ज़्यादा हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये रक्खा गया है। पहले से १,०६,७०० रुपया अधिक इसलिये रक्खा गया है कि यूनिवर्सिटियों और गैर सरकारी डिग्री कालेजों को हरिजनों की फीस माफ करने से जो नुकसान होता है उसकी एवज में ग्रांट दी जाये।

५०,००० रुपया हरिद्वार में हरि की पेड़ी के सामने एक पुल बनाने के लिये टोकेन के तौर पर रक्खा गया है। एक लाख रुपया इसलिये रक्खा गया है कि दूसरे मुल्क से आने वाले टूरिस्ट (tourists) को सुविधायें मिल सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार की बराबर इस पर नजर रही है कि बड़ी व छोटी तनख्वाहों के बीच में जो अन्तर है जहां तक हो सके उसको कम किया जाये चुनान्चे इसकी तरफ सबसे पहला कदम हुकूमत ने १९४७ ई० में उठाया जबकि पे कमेटी की सिफारिशों की बिना पर, जो गवर्नमेंट ने बिठाई थी, कम तनख्वाह पाने वालों के स्केल बढ़ाये गये। फिर भी छोटी-बड़ी तनख्वाहों में काफी अन्तर रह गया। मसलन एक चपरासी की तनख्वाह २५ रु० से शुरू होती है जिसके बरखिलाफ State की सीनियर स्केल (Senior Scale) ५०० रु० माहवार से शुरू होती है। सरकार ने अब यह फैसला किया है कि चपरासियों और उस किस्म के दीगर इन्फीरियर मुलाजमीन की तनख्वाह, पहली अप्रैल, १९५५ से २ रु० माहवार बढ़ा दी जाये। यह भी फैसला किया गया है कि १०० रु० तक तनख्वाह पाने वाले सरकारी मुलाजमीन को जो मंहगाई भत्ता मिलता है उसका आधा हिस्सा तनख्वाह का अंग कर दिया जाये। इन दोनों फैसलों के मुताबिक जिले के हेडक्वार्टर पर जो इनफीरियर मुलाजमीन तैनात होंगे उनकी तनख्वाह तकरीबन ३७ रु० माहवार से शुरू होगी। इसका असर यह होगा कि जहां एक चपरासी की शुरू की तनख्वाह और एक सीनियर स्केल अफसर की तनख्वाह में पहले १ और २० का अनुपात था वह अब घट कर १ और १३ का रह जायेगा। इस तरह से हम छोटी और बड़ी तनख्वाहों में समता (Parity) स्थापित करने में एक बड़ा क़दम आगे बढ़ा रहे हैं।

४१—मैं अब अपनी गुजारिश को इस खुशखबरी पर खत्म करता हूं कि विकास के काम का जो ब्योरा इस "स्पीच" में पेश किया गया है, वह यकीन दिलाता है कि हमारे सामने एक चमकदार भविष्य है। स्वतंत्रता के जमाने में जो "बजट" उत्तर प्रदेश में बनते रहे हैं उनके द्वारा सफलता के साथ उत्तर प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम अथक कोशिश के साथ, संतोषजनक ढंग पर होता रहा है। और यह बात बड़ी खुशी की है कि यहां की जनता ने उन कामों में जो सरकार करा रही है पूर्ण उत्साह के साथ सहयोग दिया है। कोई सरकार 'पब्लिक' के सहयोग बगैर लाभदायक कार्यों के करने में कामयाब नहीं हो सकती। सरकारें आयेंगी और जायेंगी, मगर यह हकीकत अपनी जगह कायम रहेगी कि देशों और लोगों की किस्मतों का बनना सरकार और जनता के बाहम सहयोग पर निर्भर है। मैं "लेजिस्लेचर" के सभी सदस्यों और इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास की कठिन मंजिलों के तय करने में सरकार को सहायता दी है। मैं 'अपील' करता हूं कि हम सब दुई और इख्तिलाफों को भूल कर देश के बनाने में लगें और देश की सेवा अपना कर्तव्य समझें। स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि कर्त्तव्य भी लाई है, जिसका भारी बोझ हमारे कंधों पर रखा हुआ है। इस बोझ को उठा कर हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने में सभों की खुशक़िस्मती है।

मैं आखिर में श्री बी० जी० राव, फाइनेंस कमिश्नर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले तक फाइनेंस सेक्रेट्री के पद पर बड़ी क़ाबिलियत और मेहनत से काम

किया है। सेक्रेट्री की हैसियत से राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक हालत पर कायम रखने की पूरी कोशिश की और आर्थिक मामलों में हमेशा बहुत कीमती मश्विरा दिया। उनकी जगह श्री बी० बी० लाल फ़ाइनेंस सेक्रेट्री हुए। उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फाइनेंस विभाग में मुद्दत तक ज्वाइन्ट सेक्रेट्री की हैसियत से काम किया। वह बहुत योग्य अफ़सर हैं और अपने पद का काम बेहतरीन तरीके पर अंजाम देते रहे हैं। अब सचिव की हैसियत में भी अपनी योग्यता से अपने आपको उस जिम्मेदारी के क़ाबिल साबित कर रहे हैं, जो उनके सुपुर्द की गयी है। मैं श्री बी० बी० टंडन, डिप्टी सेक्रेट्री, फाइनेंस और दूसरों का भी, जिन्होंने बजट स्पीच की तैयारी और उसके संबंधित कामों में मदद दी है, शुक्रिया अदा करता हूं। श्री एन० सी० रे और फाइनेंस विभाग के कर्मचारी भी मेरे शुक्रिये के मुस्तहक़ हैं जिन्होंने बजट की तैयारी में दिन रात काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५५-५६ का बजट पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ फरवरी, १९५५।

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३०९ एल० ए०—१९५५—७९६।